पेज : 2

पेज : 2

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

सबसे बड़ी खबर

भव्य खबर

RNI No.- DELHIN/2016/68043

नई दिल्ली संस्करण, नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 मई 2025, वर्ष : 9, अंक : 37 पृष्ठ : 08, मूल्य : 02 रुपया

नई दिल्ली से प्रकाशित व दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रसारित

संक्षिप्त समाचार

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का हुआ निधन, पार्टी में शोक की लहर

नई दिल्ली/ भव्य खबर । कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का गुरुवार को अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। करीब एक महीने पहले गणगौर के कार्यक्रम में उनकी साड़ी में आग लग गई थी, जिससे वे 90% झुलस गई थीं और सिर में भी चोट आई थी। तभी से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत गंभीर बनी रही। गिरिजा व्यास का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा और प्रभावशाली रहा है। वे मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहीं और उदयपुर से सांसद चुनी गई थीं। वे राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी थीं।

भारत की तैयारियों से घबराया पाकिस्तान, कराची - लाहौर के वायुक्षेत्र 31 मई तक किए बंद

नई दिल्ली/ भव्य खबर । भारत की तैयारियों से घबराए पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर मई महीने में कराची और लाहौर वायु क्षेत्र को रोजाना सीमित समय के लिए बंद करने की घोषणा की है। मीडिया में बृहस्पतिवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई। विमानन अधिकारियों की यह घोषणा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़े तनाव तथा नयी दिल्ली द्वारा जवाबी कार्रवाई की इस्लामाबाद की आशंका के बीच आई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र ने एक आधिकारिक नोटिस के हवाले से खबर दी, ह्यह्यसंबंधित हवाई क्षेत्र एक मई से 31 मई के बीच स्थानीय समयानुसार प्रतिदिन तड़के 4:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक बंद रहेगा।'' नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ने कहा कि बंद होने से वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन में कोई खास बाधा नहीं आएगी, क्योंकि प्रतिबंधित घंटों के दौरान विमानों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।

एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा, आज से हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर लगेगा इतना चार्ज

नई दिल्ली/ भव्य खबर । बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसे निकालना बृहस्पतिवार से महंगा हो गया है। अब बैंक महीने में मुफ्त निकासी सीमा खत्म होने पर ग्राहकों से प्रति नकद निकासी पर 23 रुपए शुल्क वसूल सकते हैं। इससे पहले बैंकों को मुफ्त निकासी सीमा से अधिक लेनदेन पर 21 रुपए तक शुल्क लेने की अनुमति थी। एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक निकासी पर लगने वाले शुल्क से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश बृहस्पतिवार से लागू हो गए हैं। ग्राहक अपने बैंक के ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) से हर महीने पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लेनदेन समेत) के लिए पात्र हैं। ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से भी सीमित संख्या में मुफ्त लेनदेन के लिए पात्र हैं। महानगरों में वे तीन निःशुल्क लेनदेन और अन्य स्थानों पर पांच निःशुल्क लेनदेन कर सकते हैं। इससे अधिक लेनदेन करने पर बैंक शुल्क वसूलते हैं। आरबीआई ने 28 मार्च को एटीएम निकासी पर शुल्क से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था। आरबीआई ने कहा था, ह्यह्यमुफ्त लेनदेन के अलावा ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपए का शुल्क लिया जा सकता है। यह एक मई 2025 से प्रभावी होगा।'' आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क को एटीएम नेटवर्क तय करेगा। सभी केंद्रों में वित्तीय लेनदेन के लिए वर्तमान इंटरचेंज शुल्क प्रति लेनदेन 17 रुपए और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए छह रुपए है। एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे बैंक के एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति देने के लिए दूसरे बैंक को देता है। आरबीआई का परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जिसमें आरआरबी, सहकारी बैंक, अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर, कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर और एटीएम परिचालक शामिल हैं।

वाराणसी जंक्शन पर दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतरा, बड़ा हादसा टला

वाराणसी/ भव्य खबर । वाराणसी जंक्शन पर गुरुवार को दुर्ग से नौतनवा जा रही दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस का इंजन शंटिंग के दौरान एक तेज आवाज के साथ डिरेल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब इंजन को प्लेटफार्म नंबर 2 से लूप लाइन की ओर ट्रैक बदलते हुए ले जाया जा रहा था। इंजन के पहिए ट्रैक से उतर गए, राहत की बात यह रही कि स्पीड कम होने के चलते घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इंजन की गति धीमी थी इस वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक तेज आवाज के साथ इंजन पटरी से उतरकर जमीन में धंस गया, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। तुरंत ही कंट्रोल रूम ने डाउन लाइन की सभी ट्रेनों को रोक दिया और कॉशन जारी किया गया। रेलवे इंजीनियरों, गैंगमैन और रनिंग स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जांच में पता चला कि इंजन के बेपटरी होने की वजह ट्रैक पर मौजूद ज्वाइंट लंप का टूटना था। जैसे ही इंजन उस हिस्से पर पहुंचा, पहिया नीचे उतर गया। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे के प्रयास के बाद इंजन को ट्रैक पर वापस लाया गया और रेल यातायात सामान्य किया गया। इस घटना के चलते कुछ ट्रेनों के संचालन में देरी हुई, लेकिन किसी तरह की जनहानि या अन्य कोई हानि होने की कोई सुचना नहीं है। राममंदिर के दरवाजों पर मढ़ा जा रहा सोना अयोध्या।राम मंदिर के दरवाजों पर फिर सोना लगाए जाने की शुरूआत हो गई है।

पीएम मोदी ने मुंबई में पहले वेव्स समिट-2025 का किया उद्घाटन

वेव्स एक ऐसा वैश्विक मंच है, जो हर कलाकार, हर निर्माता का है : मोदी

मुंबई, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स-2025) का उद्घाटन किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहां मुंबई में 100 से ज्यादा देशों के कलाकार, निवेशक और नीति निर्माता एक ही छत के नीचे जमा हुए हैं। एक तरह से आज यहां वैश्विक प्रतिभा और वैश्विक रचनात्मकता के एक ईको-सिस्टम की नींव रखी जा रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एवं एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स..ये सिर्फ एक ऐक्रोनिम नहीं है। ये एक वेब है- संस्कृति की, रचनात्मकता की। वेव्स एक ऐसा वैश्विक मंच है, जो हर कलाकार, हर निर्माता का है। जहां हर कलाकार, हर युवा एक नई योजना के साथ

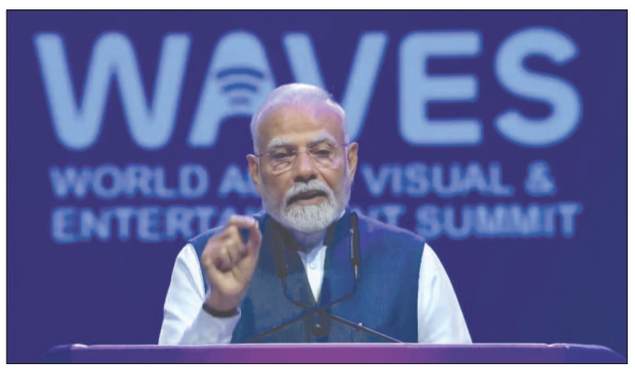

रचनात्मक दुनिया के साथ जुड़ेगा।

उन्होंने कहा कि आज 1 मई है। आज से 112 साल पहले 3 मई, 1913 को भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी, इसके निर्माता दादासाहेब फाल्के थे और कल ही उनकी जयंती थी। बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने-कोने में ले जाने में सफलता पाई है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज वेव्स में इस मंच पर हमने भारतीय सिनेमा के अनेक दिग्गजों को डाक टिकट के जरिए से याद किया है। बीते सालों में मैं कभी गेमिंग वर्ल्ड, कभी म्यूजिक की दुनिया के लोगों से, फिल्म मेकर्स से मिला, कभी स्क्रीन पर चमकने वाले चेहरों से मिला। इन चर्चाओं में अक्सर भारत की रचनात्मकता, सृजनात्मक क्षमता और वैश्विक सहयोग की बातें उठती थीं। लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले सालों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा।

वेव्स समिट 2025 में पीएम मोदी ने बॉलीवुड की पांच दिग्गज हस्तियां गुरु दत्त, पी. भानुमति, राज खोसला, ऋत्विक घटक और सलिल चौधरी पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, चुन-चुन कर लिया जाएगा बदला... पहलगाम के दहशतगर्दों को अमित शाह का कड़ा संदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को चेतावनी दी कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। पहलगाम के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में शाह ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आतंकवादियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 27 लोगों को मारने के बाद उन्होंने युद्ध जीत लिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पहलगाम में नागरिकों की हत्या करने वाले हर एक आतंकवादी की तलाश की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देगी।

शाह ने कहा कि मैं आज जनता से कहना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में आतंकवाद चलाने वालों के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से लड़ रहे हैं। आज वो (आतंकवादी) ये न सोचें कि हमारे नागरिकों की जान लेकर उन्होंने जंग जीत ली है। मैं आतंक फैलाने वालों से कहना चाहता हूं कि ये जंग खत्म नहीं हुई है, हर एक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने हर चीज का कड़ा जवाब दिया है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, वामपंथी उग्रवाद के इलाके हों या कश्मीर में आतंकवाद का साया हो।

अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर कोई सोचता है कि कायराना हमला करके उसने अपनी बड़ी जीत हासिल कर ली है, तो समझ लीजिए ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के हर एक इंच से आतंकवाद को उखाड़ फेंकना हमारा संकल्प है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की विरासत को सम्मानित करने के लिए सड़क और प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कैलाश कॉलोनी में बोडोफा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण और सड़क का उद्घाटन करने का अवसर मिला है।

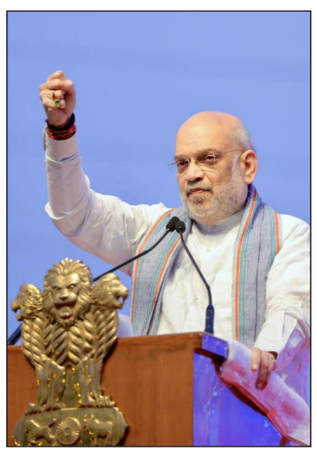

तहव्वुर बोलेगा, राज खोलेगा...

एनआईए करेगी राणा की आवाज-लिखावट के नमूने रिकॉर्ड

नई दिल्ली ।दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की आवाज और लिखावट के नमूने लेने की अनुमति दे दी है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश 30 अप्रैल को एजेंसी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। इससे पहले 28 अप्रैल को अदालत ने तहव्वुर की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। मुंबई पर 2008 में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले तहव्वुर राणा को हाल ही में भारत ले आया गया था। फिलहाल वह एनआईए की हिरासत में है। भारत पिछले 17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा था, जो कि 2009 में ही अमेरिका में गिरफ्तार हुए थे। हेडली के मामले में भारत को फिलहाल खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन तहव्वुर राणा के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी।

हमारे प्रधानमंत्री बिना समय सीमा के सुर्खियां बनाने में माहिर

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जाति जनगणना को लेकर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने गुरुवार को आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के फैसले की घोषणा के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी बिना समय सीमा के सुर्खियां बटोने में माहिर हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर सरकार की मंशा पर और मांग की कि जनगणना जल्द से जल्द होनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक बैठक में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि वह बिना समय सीमा के सुर्खियां बनाने में माहिर हैं।

रमेश ने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने कहा था हेडलाइन तो दे दी, लेकिन डेडलाइन कहां है? हमारे पीएम मोदी बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जाति जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है उसे बजट में 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन 24 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो, उद्देश्य और मंशा क्या है? सिर्फ हेडलाइन?

इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा की बाधा को हटाया जाना चाहिए। रमेश ने पूछा कि मोदी सरकार को ऐसा करने से कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि संविधान संशोधन होना चाहिए और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना तभी सार्थक होगी जब ऐसा किया जाएगा। रमेश ने दिसंबर 2019 की कैबिनेट बैठक की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में 8,254 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि उस प्रेस विज्ञप्ति में जाति गणना का कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि यह जनगणना नहीं हुई है और छह

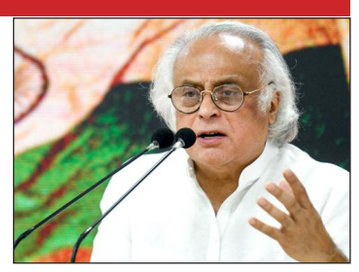

साल बीत चुके हैं। आश्चर्यजनक रूप से, सरकार ने कल ही इसकी घोषणा कर दी। हालांकि, रमेश ने सरकार से देश के सामने जाति जनगणना के लिए एक रोडमैप रखने का आग्रह किया।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की अपील

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मिले शहीद का दर्जा

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देशभर में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के दुख में साथ हैं और उनकी इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की अपील

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के दुख और उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें यह सम्मान दें।

राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी से की मुलाकात

बता दें कि इससे पहले बीते बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कानपुर में हमले के एक पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि परिवार ने उनसे कहा कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैं कानपुर में एक पीड़ित परिवार से मिला। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री

तक उनका संदेश पहुंचाएं, कि हमारे बच्चे शहीद हुए हैं और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर गंभीर है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है।

पहलगाम आतंकी हमला, एक नजर

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा कर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी।

टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी

तीन जुलाई से शुरू होने जा रही श्रीअमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है। फरवरी, 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट की रामदेव पर सख्त टिप्पणी, किसी के नियंत्रण में नहीं, अपनी ही दुनिया में जीते

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को योगगुरु बाबा रामदेव पर तीखी टिप्पणी की। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। बाबा ने हमदर्द कंपनी के रूह अफजा को लेकर शरबत जिहाद कहा था। जस्टिस बंसल ने कहा, बीते आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना ??के अंतर्गत आते हैं। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा। हम उन्हें यहां बुला रहे हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट ने रामदेव को आदेश में कहा था कि हमदर्द उत्पादों को लेकर न कोई बयान दें और न ही कोई वीडियो शेयर करें। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि कंपनी शरबत बनाती है। उससे जो पैसा मिलता है, इससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसके खिलाफ रूह अफजा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दीं।

याचिकाकर्ता को फटकार लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप सेना का मनोबल गिराना चाहते

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच से इंकार किया है। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाकर कहा कि, यह संवेदनशील समय है। पूरा देश वर्तमान में एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। क्या आप सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं। ऐसी याचिकाएं कोर्ट में मत लाइए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इसतरह की जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। देश के प्रति आप का भी कुछ कर्तव्य है। आप रिटायर्ड जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं। हम जांच (आतंकी हमले) के जानकार कब से बन गए। हमारा काम केवल फैसला सुनाना है। हालांकि कोर्ट ने कहा, स्टूडेंट की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद तीन याचिकाकर्ताओं में से एक ने याचिका वापस ले ली। जनहित याचिका कश्मीर निवासी मोहम्मद जुनैद ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में फतेश कुमार साहू और विकी कुमार का भी नाम है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

अमेरिका भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है... अमेरिकी रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद क्षति के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सचिव हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता में खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया।

बातचीत के दौरान, रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा सचिव को बताया कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण करने का इतिहास रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक समुदाय के लिए आतंकवाद के ऐसे जघन्य कृत्यों की स्पष्ट और स्पष्ट रूप से निंदा करना और उन्हें उजागर करना महत्वपूर्ण है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर अलग-अलग बातचीत की और दोनों देशों से किसी भी तनाव से बचने का आग्रह किया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अनुसार, जयशंकर के साथ बुधवार रात को फोन पर हुई अपनी बातचीत में रुबियो ने पहलगाम में ''भयावह'' आतंकवादी हमले में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सहयोग को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता जताई।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने शरीफ से इस हमले की जांच में इस्लामाबाद के सहयोग का आह्वान किया। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे। बातचीत के दौरान जयशंकर ने रुबियो से कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषियों, उनका साथ देने वालों और इसकी साजिश रचने वालों को निश्चित रूप से न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, ''कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। इसके दोषियों, उनका सहयोग करने वालों और साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।''

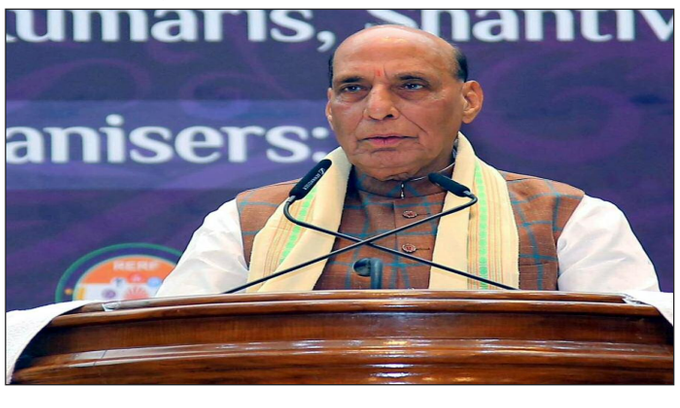

बिहार चुनाव और मोदी सरकार का जातिगत जनगणना फैसले ?

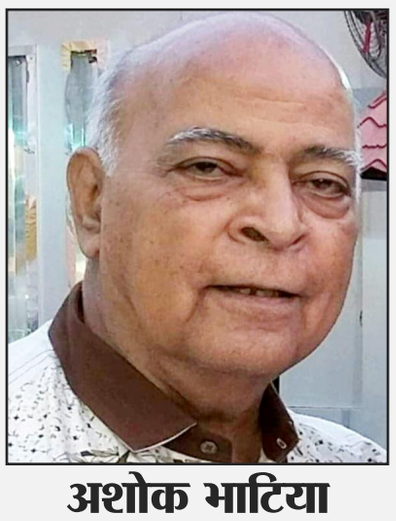

अशोक भाटिया

प्रधानमंत्री मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक कदम उठा लिया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ जाति जनगणना लागू करने की बात नहीं की है बल्कि उनकी तरफ से इस एक दांव के जरिए विपक्ष के मुद्दे को भी उनके हाथ से छीन लिया गया है। जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव लगातार अपनी हर रैली में जाति जनगणना की बात कर रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि सरकार बनने पर सबसे पहले इसी का ऐलान किया जाएगा

पहलगाम तनाव के बीच मोदी सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है, मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त तनाव है, जब इस समय हर किसी की नजर सैन्य कार्रवाई पर है, उस बीच जातिगत जनगणना पर फैसला लेकर सरकार ने सभी को हैरान कर दिया है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। अब इस एक फैसले के मायने बड़े हैं, इसे जानकार भी गेमचेंजर मानते हैं।जनगणना के आंकड़ें संवेदनशील माने जाते हैं और इनका व्यापक असर होता है। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जैसी कई योजनाएं इनपर निर्भर होती हैं। आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। जून, 2024 तक भारत दुनिया भर में उन 44 देशों में से एक था जिन्होंने इस दशक में जनगणना नहीं कराई। इसके पहले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। बताना जरूरी होगा कि भारत में जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। जनगणना से यह तो पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं लेकिन ओबीसी वर्ग में कितनी जातियां हैं, इसका पता नहीं चल पाता। वैसे देश की राजनीति ऐसी रही है कि यहां पर एक जमाना ऐसा था जब कई क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म ही जातिगत राजनीति के आधार पर हुआ। यह 1980 का दशक था जब निचली जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात हुई। यह अलग बात है कि मंडल कमीशन 1990 में जाकर लागू हुआ और उसने देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। अब विपक्षी पार्टियों को लगता है कि जातिगत जनगणना बीजेपी के हिंदुत्व का काट है। अगर हिंदू को ही बांट दिया गया तो बीजेपी के लिए अपनी सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि 'एक हैं तो सेफ हैं' की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के लिए तैयार कैसे हो गए? सुप्रीम कोर्ट में कास्ट सेंसस से बचने के लिए कई तरह की दलीलें केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी। बिहार की जातीय सर्वे की खुले मंच से आलोचना की गई थी। मगर, अब हालात बदल गए हैं। महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में कास्ट सर्वे कराने के बाद नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के पाले में हैं। वैसे, बिहार की कई योजनाओं को केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर स्वीकार किया है। उसमें अब बिहार का जातीय सर्वे भी शुमार हो गया।यही कारण है कि सरकार की ओर से फैसले की घोषणा के साथ फिर से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जहां इसे अपनी जीत बता रहे हैं वहीं भाजपा की ओर इतिहास स्पष्ट किया गया और कहा गया कि जाति जनगणना पहली बार होने जा रही है। इस फैसले के बाद एकबारगी जहां देश का ध्यान पाकिस्तान से हटकर घरेलू राजनीति पर आया वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में विपक्षी का बड़ा चुनावी मुद्दा भी छीन लिया। दरअसल अक्टूबर-नवंबर में बिहार चुनाव है जहां विपक्षी महागठबंधन इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में था। अब चुनाव में श्रेय की होड़ छिड़ेगी जहां राजग की ओर से यह बताया जाएगा कि आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना होने जा रही है। फैसले की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभिन्न राज्यों में जाति जनगणना के नाम पर जाति सर्वे पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची में जनगणना को रखा गया है, इसीलिए राज्यों ने जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। भाजपा ने जाति जनगणना को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस को आड़े हाथ लिया हैं । उनके अनुसार हकीकत यही है कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। इसका प्रमाण है कि आजादी के बाद सभी जनगणनाओं में जाति की गणना की ही नहीं गई। जाति जनगणना के मुद्दे को कांग्रेस व आइएनडीआइए गठबंधन दलों पर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में संसद में आश्वासन देने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार ने इसे नहीं कराया गया।

जाति जनगणना पर मंत्रीमंडल समूह की संस्तुति के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना के नाम सिर्फ सर्वे कराया। ध्यान देने की बात है कि जातीय जनगणना 1931 में जनगणना के साथ हुई थी। इसी जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण के लिए मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1991 में इसे लागू किया था। लेकिन पिछड़ी जातियों की मौजूदा जनसंख्या जानने और उसके अनुरूप में उनके उत्थान की नीतियां बनाने के लिए जातीय जनगणना कराने की मांग जोर पकड़ रही थी। बताया जाता है कि 2011 के सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना (एसईसीसी) से सीख लेते हुए सरकार इसका स्वरूप तय करने के लिये सर्वदलीय समिति का गठन कर सकती है। 2011 की एसईसीसी में 1931 के 4147 जातियों की तुलना में 46।80 लाख जातियां दर्ज की गई थी।इस बार सरकार जनगणना के साथ-साथ जातीय जनगणना कराने का फुलप्रूफ माडल तैयार करना चाहती है। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार इस पर आम राय बनाने की कोशिश कर सकती है और उसका सबसे अच्छा तरीका सर्वदलीय समिति का गठन है। जिसकी अनुसंशाओं के अनुरूप जातीय जनगणना कराई जाएगी। यहां पर कुछ जानकार तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक कदम उठा लिया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ जाति जनगणना लागू करने की बात नहीं की है बल्कि उनकी तरफ से इस एक दांव के जरिए विपक्ष के मुद्दे को भी उनके हाथ से छीन लिया गया है। जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव लगातार अपनी हर रैली में जाति जनगणना की बात कर रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि सरकार बनने पर सबसे पहले इसी का ऐलान किया जाएगा, अब मोदी सरकार ने समय से पहले या कहना चाहिए चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के उस मुद्दे की धार को खत्म कर दिया है।इसके ऊपर भाजपा को एक और बड़ा फायदा होने वाला है। अभी तक तो बिहार में विपक्ष द्वारा लगातार ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता रैली में इस बात का खंडन करते थे, लेकिन साथ में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जो इस बात को साबित भी कर सके। इसी वजह से राहुल से लेकर तेजस्वी तक कई बार काफी तीखे वार कर चुके थे। लेकिन अब आरक्षण विरोधी वाली छवि को भी बदलने का मौका मिल चुका है, जाति जनगणना के एक ऐलान ने बीजेपी को नई संजीवनी दे दी है, पार्टी बिहार चुनाव में अब नेरेटिव अपने मुताबिक तय करेगी। यहां पर एक और समझने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में अपने स्तर पर जाति जनगणना करवा रखी है। बिहार की जैसी राजनीति रही है, इतने सालों बाद भी बीजेपी जेडीयू की छोटा भाई बनकर रह चुकी है। पिछली विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही गई। जानकार इसका एक बड़ा कारण यह मानते हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों में नीतीश कुमार का दबदबा आज भी कायम है और बीजेपी वैश्य और सर्वण वोट बैंक के आधार पर ही राजनीति करने की कोशिश कर रही है। यहाँ यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि देश का युवा आज नौकरी मांग रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद, तमाम डिग्री लेने के बाद भी जब वो बेरोजगार रह जाता है, उसके मन में भी कई सवाल कौंधते हैं। देश की बेरोजगारी दर भी इस बात की तस्दीक करती है कि लोग ज्यादा हैं, लेकिन उतनी नौकरियां ही इस समय मौजूद नहीं। लेकिन नौकरी ना होने का एक बहुत बड़ा कारण कौशल है, अंग्रेजी में बोलें तो स्किल। आज के समय में नौकरी उसी शख्स को मिल रही है जिसके पास कोई विशेष स्किल है, जो किसी एक काम में ज्यादा ही बेहतर काम करता है।अब जरूरत स्किल की भी है, लेकिन देश में बात चल रही है जाति की, नेता सिर्फ मंथन कर रहे हैं जातिगत जनगणना पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है, वे मानकर चल रहे हैं कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, देश का असल विकास संभव नहीं, हर किसी को न्याय मिलना मुमकिन नहीं। अब जातिगत जनगणना की बात करने वाले लोगों का तर्क रहता है कि जब तक यह ना पता चले कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उन्हें ना आरक्षण का सही लाभ मिल सकता है और ना ही सरकार की दूसरी योजनाओं का।लेकिन जातिगत जनगणना की बात करने वाले यह भूल रहे हैं कि कॉरपोरेट दुनिया में युवाओं को नौकरी इस आधार पर नहीं मिल रही कि वे कौन सी जाति से आते हैं। वहां कोई यह नहीं पूछ रहा है कि आप दलित हैं तो सिर्फ आप ही को हायर किया जाएगा। उन लोगों के लिए स्किल ही सबकुछ है, अगर कुछ अलग करने का टैलेंट है, तभी हायरिंग हो रही है। उदाहरण के लिए आज के समय में देश की कई ऐसी कंपनियां सामने आ रही हैं कि जिनके लिए अकनॉलेज बहुत जरूरी है, जब तक वो नहीं, किसी की हायरिंग नहीं हो रही।

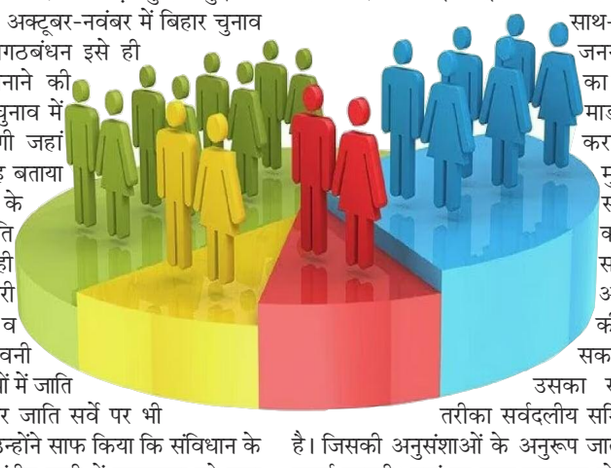

संपादकीय

मोदी का आक्रोश

अमृता आर. पंडित

कश्मीर के पहलगाम में 27 लोगों की नृशंस हत्या से पूरे देश में उबाल है। स्वाभाविक तौर पर देश का हर नागरिक इस हत्याकांड़ का बदला लेने की बात कह रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में पाकिस्तान के प्रति अपने आक्रोश को साझा किया। उन्होंने कहा कि, 'आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे मन में गहरी पीड़ा है। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुःख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। चाहे वह किसी भी राज्य का हो या किसी भी भाषा बोलता हो, हर भारतीय उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है, जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे यह महसूस हो रहा है कि हर भारतीय का खून इस आतंकवादी हमले को देखकर खौल रहा है।' मोदी यह जानते-समझते हैं कि देश इस समय बेहद नाजुक दौर में है। आमजन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ऐसे क्षण में बहुत संजीदगी से कोई भी कदम उठाने की दरकार है। पाकिस्तान को कैसे न भूलने वाला सबक सिखाया जाए, केंद्र सरकार इसी को लेकर रणनीति बनाने में दिन-रात एक किए हुए है। यह हमला कश्मीर में होते रहे हमलों से भिन्न है। हालांकि 'टारगेट किलिंग' पहले भी होती रही है, मगर इस बार धर्म पूछकर गोली मारने की वारदात नितांत हटकर है। जाहिर है आतंकवादियों और पाकिस्तान का मंसूबा भारत में धार्मिक जहर फैलाना था। दूसरी अहम बात यह भी है कि पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा और कायरता को दशार्ता है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल-कॉलेजों में एक नई ऊर्जा थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी और युवाओं के लिए नये अवसर तैयार हो रहे थे, तो यह स्थिति देश और जम्मूकश्मीर के दुश्मनों को पसंद नहीं आई। वे नहीं चाहते थे कि कश्मीर में विकास और शांति का यह माहौल कायम रहे। मोदी ने अपने संबोधन में बेहद संतुलित और गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहकर कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, यह संकेत दे दिया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। देखना है, भारत की जवाबी कार्रवाई किस तरह की होती है। बारम्बार निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों को इस बार भारत कुछ ऐसा जवाब दे कि वह दोबारा ऐसा करने की सोचे भी नहीं।

चिंतन-मनन

सबसे बड़ी दौलत

एक विधवा अध्यापिका के दो बेटे थे। वह उन्हें गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वह खुद भी अनेक बच्चों को संस्कृत पढ़ाती थी। इससे उसे जो कुछ प्राप्त होता था, उसी से वह अपना जीवनयापन करती थी। उसने अत्यंत गरीबी के दिनों में भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उसके स्वाभिमान को देख अनेक लोग अध्यापिका का बहुत आदर करते थे। एक दिन एक बहुत बड़े सेठ को अध्यापिका की विद्वता व उसकी निर्धनता के बारे में मालूम हुआ। उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा हुआ था कि वह कुछ गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें धन प्रदान करेगा। सेठ अध्यापिका के घर पहुंचा और बोला, देवी, आप निर्भीक व स्वाभिमानी हैं। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। उसके लिए आप यह कुछ रुपये स्वीकार करें। इसके बाद उसने रुपयों की थैली अध्यापिका की ओर बढ़ाई। अध्यापिका हाथ जोड़कर सेठ से बोली, शायद आपको कुछ भ्रम हो गया है। मैं इतनी गरीब भी नहीं हूं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे पाऊं। मेरे पास जितनी दौलत है, उतनी शायद ही किसी के पास हो। सेठ अचरज से बोला, कहां है दौलत, जरा हमें भी तो बताइए। अध्यापिका ने अपने दोनों पुत्रों को आवाज लगाई तो दोनों पुत्र तुरंत वहां आए और अपनी मां के पैर छूने के बाद उन्होंने सेठ के पैर छुए। फिर उन्होंने मां से पूछा, कहिए कैसे याद किया? दोनों पुत्रों की ओर देखकर अध्यापिका बोली, यही दोनों मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। दोनों लड़कों को देखकर सेठ अभिभूत हो गया और बोला, बिल्कुल सही। वास्तव में जिसकी संतान संस्कारी और गुणी है, वह कभी गरीब हो ही नहीं सकता। अध्यापिका ने सेठ से कहा, जो कुछ आप मुझे देने आए हैं, उसे अनाथ बच्चों को शिक्षित करने के लिए दे दें। सेठ ने वैसा ही किया।

श्रम का सम्मान ही सच्ची प्रगति का आधार

यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि श्रम की गरिमा, अधिकारों की लड़ाई और समाज में कार्यशील वर्ग के महत्व की चेतना का प्रतीक है। इतिहास के पन्नों में झाँकें तो यह दिवस हमें उन्नीसवीं सदी की उन क्रांतियों की याद दिलाता है, जब श्रमिक वर्ग ने अपने श्रम के सम्मान और मानवाधिकारों के लिए आवाज बुलंद की थी, यह वह ऐतिहासिक स्मृति है, जो समाज की रीढ़ माने जाने वाले श्रमिक वर्ग के संघर्ष, बलिदान और चेतना की कहानी कहता है। यह दिन हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या वास्तव में हमारे समाज ने श्रमिक को वह गरिमा और अधिकार दिए हैं, जिसका वह हकदार है ?कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी में यूरोप में फैले सामाजिक असंतुलन और पूंजीवादी शोषण की पृष्ठभूमि में "दास कैपिटल" और "कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो" जैसे ग्रंथों के माध्यम से पूरी दुनिया को श्रमिक वर्ग की शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने लिखाः

"The history of all hitherto existing society is the history of class struggles."

मार्क्स ने चेताया कि जब यह वर्ग अपनी स्थिति को पहचानकर संगठित होगा, तब एक ऐसी क्रांति होगी जो शोषण पर आधारित समाज को जड़ से बदल डालेगी। मजदूर दिवस की आत्मा उसी क्रांति की गूंज है। मार्क्स ने समाज के ढांचे को दो वर्गों में विभाजित किया - बुर्जुआ (पूंजीपति) और प्रोलितारियत (मजदूर)। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों का शोषण कर लाभ अर्जित करती है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'दास कैपिटल' में यह स्पष्ट किया गया कि कैसे श्रम, उत्पादन का मूल आधार होते हुए भी, सबसे उपेक्षित रह जाता है, मार्क्स ने ह्यऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया कि इतिहास की दिशा उत्पादन के साधनों पर आधारित वर्ग-संघर्ष से तय होती है। उनकी सोच ने आगे चलकर मजदूर आंदोलनों को वैचारिक संबल दिया। 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में हजारों श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्यदिवस की मांग को लेकर विशाल रैली की। जब पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, तो कई मजदूर शहीद हो गए। यह घटना इतिहास में हे मार्केट नरसंहार के नाम से दर्ज हुई, हे मार्केट में जो घटना घटी, वह इतिहास में मजदूरों के आत्मसम्मान की सबसे मुखर आवाज बनकर उभरी, शहीदों की स्मृति में 1889 में द्वितीय इंटरनेशनल की पेरिस कांग्रेस ने 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया। उस दिन से लेकर आज तक, यह दिवस दुनिया भर के श्रमिकों की एकता, अधिकार और सम्मान का प्रतीक बन चुका है, यह महज अमेरिका की घटना नहीं थी, बल्कि उस लहर की शरूआत थी जिसने यूरोप, एशिया और फिर भारत को भी प्रभावित किया। लेनिन से लेकर नेहरू तक, और फिर डॉ. लोहिया व जे.पी. नारायण जैसे विचारकों ने भारतीय संदर्भ में श्रमिक आंदोलनों को नई दिशा दी, भारत में मजदूर आंदोलन की नींव ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ी। रेलवे, कपड़ा उद्योग और कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों की दयनीय स्थिति ने धीरे-धीरे संगठनों और यूनियनों को जन्म दिया, मजदूर आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ जन्म लिया, 1920 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना ने श्रमिक संगठनों को वैचारिक और रणनीतिक बल प्रदान किया। महात्मा गांधी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, डॉ. आंबेडकर की वेतन आयोगों के लिए आवाज, और स्वतंत्र भारत में पं. नेहरू का योजनात्मक आर्थिक ढांचा, सभी ने श्रमिक वर्ग को केंद्रीय भूमिका दी, स्वतंत्रता के बाद संविधान ने भी मजदूरों को अधिकार दिए न्यूनतम वेतन, कार्य के घंटे, सामाजिक सुरक्षा आदि।

आज जब भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, तब भी एक श्रमिक की जिंदगी संघर्षों से भरी है:

गिग इकॉनमी में कार्यरत श्रमिक जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर आदि के पास न श्रमिक अधिकार हैं, न बीमा सुरक्षा, मनरेगा जैसी योजनाएँ ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान हैं, पर कार्य के दिन सीमित हैं और भुगतान में देरी आम है। प्रवासी मजदूर संकट (विशेषकर कोविड-19 के दौरान) ने दिखाया कि हमारे पास श्रमिकों के लिए आपातकालीन संरचना कितनी कमजोर है, यह दिन हमें उस मूलभूत सवाल से जूझने का अवसर देता है किसके श्रम से यह समाज चलता है, और क्या उस श्रम को वह मान-सम्मान मिल रहा है, जिसके वह योग्य है? एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिक को कितनी गरिमा देता है। और जब तक मजदूर को सामाजिक सुरक्षा, स्थिर रोजगार और सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक भारत की विकास गाथा अधूरी रहेगी, मजदूर दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ नीतियों से नहीं, पसीने से होता है, आज जब वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर परिवर्तन के दौर में है – ऑटोमेशन, गिग इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसी व्यवस्थाएँ श्रमिकों के लिए नए अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियाँ भी लेकर आई हैं। संगठनों की संख्या घटी है, और श्रमिकों की आवाजें बिखरती जा रही हैं,ऐसे में हमें फिर से यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता, जब तक उसके श्रमिक वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और सहभागिता न मिले।

योगेन्द्र सिंह

राजेश श्रीवास्तव

अवध बार एसोसिएशन

अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित संगठन है। इसकी स्थापना केवल अधिवक्ताओं के एक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विधिक सुधारों को प्रोत्साहित करने और अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के पवित्र उद्देश्य से की गई थी। 120 वर्षों से अधिक के अपने गौरवशाली इतिहास में, इस संस्था ने भारतीय न्यायपालिका को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संगठन न केवल विधिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि न्याय की रक्षा के लिए अडिग संघर्ष का भी उदाहरण है। अवध बार एसोसिएशन ने हमेशा न्यायपालिका में सुधारों और विधिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के लिए संघर्ष किया है। इसका इतिहास आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और ठोस निर्णयों से भरा हुआ है, जो न्याय के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं। फरवरी 2021 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार और न्यायाधिकरणों की स्थापना की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। फरवरी 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की भारी कमी और बढ़ते लंबित मामलों के विरोध में कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया, जिससे सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने को विवश होना पड़ा। मार्च 2025 में लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र में अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद के विरोध में एसोसिएशन ने एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। यह कदम न केवल अधिवक्ताओं की एकजुटता को प्रदर्शित करता है, बल्कि उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रति एसोसिएशन की अटूट प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है। इस संस्था ने भारतीय न्यायपालिका को कई प्रतिष्ठित न्यायविद और विधि विशेषज्ञ प्रदान किए हैं, जिनके निर्णयों और योगदानों ने न्यायिक प्रणाली को नई दिशा दी है। न्यायमूर्ति ए.बी. सिंह ने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका में पारदर्शिता स्थापित की, जबकि न्यायमूर्ति सी.डी. शर्मा संवैधानिक मामलों में निष्पक्ष दृष्टिकोण और विधिक विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हुए। न्यायमूर्ति डी.पी. सिंह राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, न्यायमूर्ति आर.एस. यादव ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, और न्यायमूर्ति एस.के. गुप्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। अवध बार एसोसिएशन का नेतृत्व हमेशा बार और न्यायपालिका के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य करता आया है। विभिन्न अध्यक्षों और महासचिवों ने संस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। अक्टूबर 2021 में, राकेश कुमार चौधरी अध्यक्ष बने, जो 120 वर्षों में इस पद पर पहुँचने वाले आरक्षित वर्ग के पहले अधिवक्ता थे। फरवरी 2023 में आनंद मणि त्रिपाठी को अध्यक्ष और मनोज कुमार मिश्रा को महासचिव चुना गया। वर्तमान में, वर्ष 2025 में, श्री आर.डी. शाही अध्यक्ष एवं श्री मनोज कुमार द्विवेदी महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। इनके नेतृत्व में अवध बार एसोसिएशन ने ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय लिए, जिससे बार की गरिमा और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।अवध का इतिहास प्राचीन और समृद्ध रहा है। यह क्षेत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, जिनके पूर्वजों ने अवध की स्थापना की थी। श्रीराम के 121 पूर्वजों और वंशजों का विस्तृत वर्णन लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ प्रदर्शित राजकीय चिन्ह रामायण काल के साक्षी माने जाते हैं। लखनऊ की स्थापना को लेकर दो मान्यताएँ प्रसिद्ध हैं–एक मान्यता के अनुसार इसकी स्थापना भगवान श्रीराम के अनुज लक्ष्मण ने की थी, इसलिए इसे पहले "लक्ष्मणपुर" कहा जाता था। दूसरी मान्यता के अनुसार, 11वीं सदी के एक शासक महाराजा लाखन पासी ने इसकी स्थापना की थी। अवध में न्यायिक प्रणाली की नींव ब्रिटिश शासन के दौरान रखी गई थी। 19वीं शताब्दी में "चीफ कोर्ट ऑफ अवध" की स्थापना हुई, जो बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के रूप में स्थापित हुआ। अवध बार एसोसिएशन की स्थापना 19 मई 1901 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की मजबूती और अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना था।

अवध बार एसोसिएशन की यात्रा केवल एक संगठन के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह न्याय, निष्ठा और विधिक उत्कृष्टता की अमिट गाथा है। इस संस्था ने न केवल अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की है, बल्कि न्यायपालिका में सुधार और समाज में न्याय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके आंदोलनों, संघर्षों और विधिक प्रयासों ने न्यायिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी बनाने में योगदान दिया है। भविष्य में भी अवध बार एसोसिएशन अपनी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ न्यायपालिका के उत्थान और विधिक सुधारों की दिशा में कार्य करता रहेगा, जिससे देश में एक सशक्त, निष्पक्ष और आधुनिक न्यायिक प्रणाली स्थापित हो सके।

संक्षिप्त डायरी

स्वच्छता को लेकर हुई बैठक से होंगे बदलाव : सिरसा

नई दिल्ली/ भव्य खबर । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरूवार को सचिवालय में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आज पहली बार दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार के तहत एलजी के साथ पहली मीटिंग हुई. दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अधिकारी, डीडीए के अधिकारी, सभी जिलों के डीएम और डीसीपी मौजूद रहे. दिल्ली में अब बड़े स्तर पर एक सफाई अभियान चलाया जाएगा. सभी विभाग और एजेंसियां इसमें मिलकर काम करेंगी. सभी निगम जोन के डीसी और डीएम को अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी दी गई है. सभी की जवाबदेही तय की गई है. 20 दिन का दिल्ली में एक व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अभियान शुक्रवार से शुरू होगा. 20 दिन का यह अभियान वर्षों के लंबित काम को पूरा करेगा, यह पीएम मोदी के विजन को पूरा करेगा. दिल्ली की जनता को यह जरूर महसूस होगा कि उन्होंने अपने बटन की ताकत से जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है वह काम कर रही है. दिल्ली में कचरे के सेग्रीगेशन का काम व्यापक स्तर पर शुरू होगा, अधिकारियों को भी एसी कमरों से निकलकर अब क्षेत्र में दौरा करना ही होगा. रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली का हर एक कोना हर एक सड़क पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. हर विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है. सेफ्टी में अगर लेप्स होता है तो डीसीपी की जिम्मेदारी होगी. उन्होंने कहा कि हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि दिन में दो बार सफाई सुबह 8 बजे और फिर शाम को सफाई होगी. दो बार दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा ताकि पूरा शहर दिल्ली सुंदर दिखे और लोगों को फर्क दिखे. सीएम ने कहा कि बेहतर दिल्ली और सुंदर दिल्ली बनाने का हमारा लक्ष्य है. दिल्ली में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होगा. कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं रहेगा. किसी भी प्रकार की दीवारों पर पोस्टर राइटिंग नहीं होगी, जो यह काम करेंगे उन पर जुमार्ना लगाया जाएगा. इसके साथ ही धार्मिक स्थल और बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

नई दिल्ली/ भव्य खबर । दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में नरेश बालियान के साथ-साथ जयोति प्रकाश, साहिल, और विजय उर्फ कालू को भी आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट कल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के संबंध में विचार करेगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेश बालियान को 4 दिसंबर 2024 को एक कथित जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें मकोका के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि बालियान का कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ संबंध है, जो दिल्ली-एनसीआर में जबरन वसूली और टारगेट किलिंग जैसे संगठित अपराधों में शामिल है। इस मामले में एक वायरल ऑडियो क्लिप भी जांच का हिस्सा है, जिसमें बालियान और सांगवान के बीच कथित बातचीत का दावा किया गया है। शुक्रवार की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इस मामले में अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ भी पूरक चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। नरेश बालियान उत्तम नगर से आप के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई जारी है।

वेटिंग टिकट वालों को नहीं मिलेगी स्लीपर और AC कोच में एंट्री

नई दिल्ली/ भव्य खबर । भारतीय रेलवे ने यात्रियों की यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आज यानी 1 मई 2025 से एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। अब यदि आपके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है, तो आप स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। ऐसे यात्रियों को केवल जनरल क्लास में ही यात्रा करने की अनुमति होगी। रेलवे की ओर से साफ किया गया है कि यदि आपने क्ष्ळ्ळ्उ से ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक किया है और वह कन्फर्म नहीं होता, तो वह स्वतः रद्द हो जाएगा। उस स्थिति में यात्री को ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट अभी भी रद्द नहीं होते, लेकिन अब ऐसे यात्री भी आरक्षित डिब्बों में नहीं बैठ सकेंगे। रेलवे ने साफ किया है कि यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में पाया गया, तो टीटीई को उस पर जुमार्ना लगाने या जनरल डिब्बे में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। यह नियम यात्रियों के बीच अनुशासन और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। वहीं, अब यदि आप वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो अब आपको यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि बिना आरक्षण आप केवल जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने कहा कि यह निर्णय उन यात्रियों के हित में लिया गया है जो कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा- वेटिंग टिकट यात्रियों के कारण आरक्षित डिब्बों में भीड़ और अव्यवस्था होती है, जिससे कन्फर्म यात्रियों को असुविधा होती है। नए नियम से इस स्थिति में सुधार होगा । रेलवे के मुताबिक, वेटिंग टिकट वाले यात्री अक्सर आरक्षित कोचों में जबरन घुस आते हैं, जिससे सीटों पर कब्जा करने की कोशिशें होती हैं और चलने के रास्ते तक बंद हो जाते हैं। इससे सभी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नया नियम इस समस्या पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

दिल्ली हाट में भीषण आग; 26 दुकानें खाक, सरकार ने दिया मदद का भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में बुधवार रात को भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद दमकल की 14 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। आग की चपेट में आकर 26 दुकानें जलकर खाक हो गईं। बचाव के काम में कुछ लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा मौके पर पहुंचे और दिल्ली सरकार की ओर से पीड़ित व्यापारियों को हर तरह से मदद किए जाने का भरोसा दिया।

पुलिस का कहना है कि आग को पूरी तरह से बुझा दिए जाने के बाद तलाशी अभियान चलाया जाएगा, इसके बाद ही नुकसान की सही तस्वीर सामने आएगी। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना करीब नौ बजे मिली थी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इस दौरान सरोजनी नगर थाने से भी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

भीड़ होती तो बड़ा रूप ले लेता हादसा

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग रात में लगी। आग लगने के समय हाट में भीड़ नहीं थी। यदि भीड़ होती तो यह हादसा भयानक रूप ले लेता। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि समय से आग को फैलने से रोक दिया गया। आग पर काबू पा लिया गया है।

रेखा सरकार ने दिया मदद का भरोसा

दिल्ली हाट में आग लगने की घटना पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- आग लगने की खबर मिलते ही अधिकारी, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचे। आग में करीब 26 दुकानें जल गई हैं। फूड प्लाजा की तरफ भी कुछ और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सीएम रेखा गुप्ता ने मुझे यहां भेजा। मैं सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है।

आर्थिक मदद का वादा, हादसे की होगी जांच

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- आग में अपनी दुकानें खोने वाले व्यापारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सभी कारोबारियों की दुकानें फिर से लगाई जाएंगी। हम आग लगने की वजहों की जांच करेंगे। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी कमियां सामने आएंगी। उन पर विचार किया जाएगा। सरकार सख्त कदम उठाएगी।

तेजी से फैली आग, करोड़ों का नुकसान

दिल्ली हाट के एक दुकानदार ने कहा- आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग में करीब 27 से 28 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी क्योंकि आग लगने से पहले अचानक लाइट चली गई थी। आग बहुत तेजी से फैली। इसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

व्यावसायिक इमारतों में शुरू हुई जांच

इस बीच दिल्ली में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। एमसीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजधानी की सभी व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच शुरू कर दी है।

नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस होगा कैंसिल

नियमों को उल्लंघन करने वाले रेस्तरां, होटल और खाने पीने से जुड़ी दुकानों के संचालकों का लाइसेंस रद्द करने पर भी फैसला लिया जाएगा। बीते वर्ष दिसंबर में राजौरी गार्डन में एक रेस्तरां में आग लगने की घटना के बाद कई रेस्तरां को सील कर दिया गया है। इस साल अप्रैल तक ऐसे 80 से अधिक रेस्तरां को सील किया गया है।

करोड़ों का हुआ नुकसान

दिल्ली सरकार के अफसरों का कहना है कि अलग-अलग राज्यों के लोग यहां पर अपने अपना स्टॉल लगते हैं और करीब 25 से 30 स्टॉल आग की चपेट में आ गए। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली हाट के दुकानदार एजाज हुसैन ने बताया कि आग में उनकी लखनवी चिकनकारी के अलावा 95 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। उन्होंने बताया- 'हमारी दुकान में शानदार लहंगे थेज्एक धागा भी नहीं बचाज् अल्लाह का शुक्र है कोई मरा नहीं।' एक अन्य दुकानदार ने कहा- 'आग लगने के 45 मिनट बाद दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी आएज् उनका स्टेशन सिर्फ तीन मिनट की दूरी पर है। कई बार उनका फोन भी नहीं मिल पाता था।'

मुख्यमंत्री ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन स्थिति पर करीबी निगरानी रख रहा है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, 'दिल्ली हाट में आग की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर नियंत्रण पाया। अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रभावितों को सभी आवश्यक सहायता दी जा रही है।'

भीड़भाड़ का फायदा उठाकर स्नैचिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। थाना बाड़ा हिंदू राव पुलिस टीम ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है जो भीड़भाड़ का फायदा उठाकर लोगों को निशाना बनाता था। पकड़ा गया आरोपी गोलू है। पुलिस ने इसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। उत्तरी जिला डीसीपी राजा बॉठिया ने बताया कि थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव रंजन की देखरेख में गठित टीम ने जांच के दौरान स्थानीय खुफिया जानकारी एकत्र की गई। पुलिस टीम के अथक प्रयासों के बाद, यह पता चला कि गोलू नामक व्यक्ति ने यह स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन वह पिछले कुछ दिनों से फरार था। पुलिस टीम द्वारा लगातार छापेमारी के बाद, डीसीएम रोड, किशन गंज रेलवे स्टेशन, दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। आरोपी ने शिकायतकर्ता सोमवीर के साथ उस समय वारदात को अंजाम दिया जब वह अपने दोपहिया वाहन से खरीदारी करने के लिए खारी बावली आया था। पूछताछ के दौरान आरोपी गोलू ने खुलासा किया कि वह अपनी मां के साथ पीली कोठी, पुल मिठाई, दिल्ली के फुटपाथ पर रहता है। वह अनपढ़ है और स्मैक का आदी है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह आस-पास के इलाकों में अपराध करता था। पिछले कुछ महीनों से वह राहगीरों से झपटमारी करने लगा था, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। उसने यह भी खुलासा किया कि उक्त वारदात को अंजाम देने के बाद वह पुलिस से बचने के लिए पिछले कुछ दिनों से उस इलाके में नहीं आया था।

दिल्ली सरकार ने 20 दिवसीय स्वच्छता अभियान की घोषणा की

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 20 दिवसीय व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू करने की घोषणा की। सरकार का लक्ष्य शुक्रवार से शुरू होने वाले इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर 'कचरा पृथक्करण' को लागू करना, अतिक्रमण हटाना और दैनिक निगरानी सुनिश्चित करना है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की अध्यक्षता में राजनिवास में आयोजित बैठक के बाद यह घोषणा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत जिलाधिकारियों, उपायुक्तों, पुलिस उपायुक्तों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हर धार्मिक स्थल, बाजार और स्कूल को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। धूल से प्रभावित इलाकों को पौधरोपण के जरिए हरा-भरा किया जाएगा और रोजाना सुबह आठ बजे और शाम को सफाई की जाएगी।''

गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नगर निकाय अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, ''प्रत्येक शीर्ष अधिकारी को प्रतिदिन अपने संबंधित क्षेत्र का दौरा करना होगा और अपने विभाग प्रमुख को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। सार्वजनिक मार्गों, पार्कों या बाजारों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, मलबा या कचरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्टर या भित्तिचित्र के माध्यम से दीवारों को विरुपित करने पर सख्त दंड का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी चूक के लिए जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त सहित सभी शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

केंद्र और राज्य के साथ-साथ नगर निगम में भी भाजपा की सरकार होने का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, ''ट्रिपल इंजन वाली सरकार के आगमन के साथ दिल्ली ऐतिहासिक अवसर का गवाह बन रही है। 'ट्रिपल इंजन' वाली सरकार के तहत यह अभियान वर्षों के गतिरोध को तोड़ देगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने के अनुरूप दिल्ली स्वच्छ, हरित और अधिक सुंदर होगी।''

नरेला में 50 एकड़ में बनेगा आईजीडीटीयूडब्ल्यू का स्थाई परिसर: आशीष सूद

नई दिल्ली (एजेंसी)। नरेला में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू) का स्थायी परिसर बनेगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। उक्त बातें दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू) के स्थापना दिवस समारोह और रिसर्च एक्सीलेंस अवॉर्ड्स के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को 50 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा मिल चुका है। यह जमीन दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित की गई है और अब यहां विश्वविद्यालय का बहुप्रतीक्षित स्थायी परिसर बनेगा। उन्होंने कहा कि नरेला में 50 एकड़ जमीन का कब्जा मिलना सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह महिला शिक्षा और नेतृत्व में एक दीर्घकालिक निवेश है।

अब दिल्ली महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र बनकर उभरेगी। कश्मीरी गेट स्थित वर्तमान 10 एकड़ के सीमित परिसर में संचालित होने वाले इस महिला तकनीकी विश्वविद्यालय को देश-विदेश में महिला नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नया कैंपस महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण बनेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार एक महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप और रिसर्च हब की भी योजना बना रही है, जहां महिलाओं को संसाधन, पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. रंजना झा ने कहा कि यह भूमि एक भविष्य-दर्शी कदम है, जो एक समावेशी और विश्वस्तरीय परिसर के निर्माण की ओर बढ़ाया गया है। हम शिक्षा मंत्री आशिष सूद और उपराज्यपाल एवं कुलाधिपति विनय कुमार सक्सेना का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि नए परिसर में स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, सतत विकास, समावेशी शिक्षा और छात्र-केंद्रित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस नए परिसर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु तकनीक, रोबोटिक्स, शहरी नियोजन, कानून और नीति जैसे उभरते क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि महिलाएं भविष्य की तकनीकी दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा सकें। सम्मानित की गई छात्राएं स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के रिसर्च एक्सीलेंस अवॉर्ड्स भी प्रदान किए गए, जहां फैकल्टी और छात्राओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों, पेटेंट और नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया।

करोड़ों का व्यापार फर्जीवाड़ा करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय व्यापार फर्जीवाड़ा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जाली बिल ऑफ लैडिंग (बीएल) और अन्य नकली शिपिंग दस्तावेज बनाने के आरोप हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा मुकेश गुप्ता सिंगापुर का नागरिक है। वह ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारक है। आरोपी के खिलाफ वर्ष-2022 में ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया था। राजनयिक प्रोटोकॉल के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दिल्ली स्थित सिंगापुर उच्चायोग को दी गई है। ईओडब्ल्यू की डीसीपी अमृता गुगलोथ के मुताबिक, मेसर्स चौधरी टिम्बर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (सीटीआईपीएल) की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि न्यूजीलैंड से लकड़ी आयात करने के लिए मुकेश गुप्ता के प्रतिनिधित्व वाले मेसर्स एमरोज सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड से एक समझौता किया था। भुगतान भारतीय बैंक, सिंगापुर के माध्यम से लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के माध्यम से किया गया था। इसके बाद पता चला कि आरोपियों द्वारा जाली बीएल और नकली शिपिंग दस्तावेज बैंक में लगाए गए। इन्हें दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया की कनॉट प्लेस शाखा को भेजा गया था। इन जाली दस्तावेज के आधार पर बैंक ने लगभग 10 करोड़ रुपये जारी किए, लेकिन कभी कोई शिपमेंट नहीं किया गया। जांच में पता चला कि बीएल मार्च 2020 में भारतीय बैंक, सिंगापुर के माध्यम से भेजे गए थे। जहाज मालिक (एशिया मैरीटाइम पैसिफिक लिमिटेड), शिपिंग एजेंट (अर्नव शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड) और बीमाकर्ता (वेरो इंश्योरेंस, न्यूजीलैंड) से सत्यापन से पुष्टि हुई कि बीएल नकली थे और एमवी एशिया पर्ल-द्ब भारत के लिए ऐसा कोई शिपमेंट नहीं ले गया था। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया से जाली दस्तावेज जब्त कर आरोपी को 22 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता का शिपिंग एजेंट के अधिकृत प्रतिनिधि से भी आमना-सामना कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि कंपनी के नाम और मुहर का इस्तेमाल आरोपी ने धोखाधड़ी से किया था। उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है आरोपी आरोपी मुकेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। उसने 1978 में रोहिलखंड विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी। 1986-87 में वह गुजरात चला गया और लकड़ी का व्यापार शुरू किया। 1995-96 में इंडिया ओवरसीज लॉन्च किया। 2003 में, उसने मेसर्स एमजी फॉरेस्ट की स्थापना की, जिसे बाद में मेसर्स एमरोज सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में था। कंपनी मलेशिया, इंडोनेशिया, घाना और नाइजीरिया सहित 20 से अधिक देशों में काम करती थी।

स्कूलों में बम धमकियों पर एसओपी : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूलों में बम की धमकी जैसी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र तैयार करने में विफलता का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर बृहस्पतिवार को सरकार के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि इस पर प्राधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर तब जब फर्जी कॉल आना बहुत आम बात हो गई है और इससे बच्चे, उनके अभिभावक और स्कूल परेशान हो रहे हैं। न्यायमूर्ति दयाल के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया कि प्राधिकारी न्यायालय के 14 नवंबर 2024 के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, जिसमें उन्हें ऐसे मामलों से निपटने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश में सरकारी एजेंसियों और पुलिस को निर्देश जारी होने के आठ सप्ताह के भीतर तंत्र विकसित करने की आवश्यकता बताई गई थी। अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले पर अद्यतन जानकारी मांगी और अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की। अदालत ने तब सरकार और पुलिस अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने अपनी याचिका में राजधानी के स्कूलों को बार-बार बम धमकी वाले ई-मेल मिलने के संबंध में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आठ सप्ताह की अवधि 14 जनवरी, 2025 को समाप्त हो गई, लेकिन अदालत के आदेश के अनुरूप किसी विस्तृत कार्य योजना या एसओपी के निर्माण या कार्यान्वयन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई।

इंटरनेशनल लेबर डे : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं, आज की सरकार श्रमिकों के बारे में सोचती है

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर श्रमिकों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले महज अपने हित साधने के प्रयास किए जाते थे और देश की नींव कहे जाने वाले श्रमिकों के हितों पर हमेशा से ही कुठाराघात किया जाता था।

उन्होंने कहा, 'यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्र है कि उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले श्रमिकों के कल्याण के बारे में सोचा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस देश के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति की जाए, यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि वह खुद एक गरीब परिवार से आते हैं। वह गरीबों का दर्द जानते हैं। वह जानते हैं कि एक गरीब परिवार की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अपने जीवन में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'पहले कभी श्रमिकों को इस देश में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता था। लेकिन, आज मैं सभी श्रमिक भाइयों को यह विश्वास दिलाती हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी को इस देश में वही समान अधिकार मिलेंगे, जो अन्य नागरिकों को मिलते हैं। जितना अधिकार इस देश में किसी करोड़पति आदमी का है, उतना ही आप लोगों का भी है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अब आपके सम्मान, अधिकार और हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आपको हर वह सम्मान मिलेगा, जो इस देश के संविधान में दिए जाने का प्रावधान है, क्योंकि मौजूदा समय में इस देश और राज्य में भी एक ऐसी सरकार है, जो आपके हितों के बारे में दिन-रात सोचती है और हम आपके हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होने देंगे।'

वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने भी पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बार श्रमिकों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकार श्रमिकों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती थी, वह कर सकती थी, लेकिन उनके अंदर श्रमिकों के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं थी, मगर मैं आज अपने सभी मजदूर भाइयों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यह सरकार आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। यह एक ऐसी सरकार है, जो आपके बारे में सोचती है। आप हमारे लिए हमारा परिवार हैं।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया है कि श्रमिकों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को श्रमिकों को मजबूत करने का प्रयास किया गया। कानून के तौर पर कई ऐसे प्रावधान किए गए, जिससे श्रमिकों को समृद्ध किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के श्रम में शक्ति है। आपके श्रम से ही यह देश विकास की गति पकड़ेगा। आप लोग ही इस देश की नींव हैं।

संक्षिप्त डायरी

पीएम मोदी की फोटो पर विवाद : कांग्रेस बन गई लश्करे पाकिस्तान और सपा है हिंदू द्रोही- प्रेम शुक्ला

सुलतानपुर/ भव्य खबर। भारतीय जनता पार्टी के प्र-वक्ता प्रेम शुक्ला ने बुधवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सुलतानपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अब लश्करे पाकिस्तान बन चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी मानसिकता की परिचायक बन गई है। प्रेम शुक्ला की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किए गए एक विवादित फोटो को लेकर आई, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कांग्रेस के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं और संयुक्त राष्ट्र में राहुल गांधी के बयानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, हिंदुओं द्वारा हिंदुओं को मारने का एकमात्र उदाहरण तब मिला जब मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था। यह घटना सपा की असली मानसिकता को दशार्ती है। प्रेम शुक्ला ने राम गोपाल यादव, रॉबर्ट वाड्रा और सिद्धारमैया पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये नेता देश के भीतर रहकर पाकिस्तान समर्थक रवैया अपनाते हैं। उन्होंने पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की टारगेटेड हत्या की घटना का ज़िक्र कर कहा कि धर्म के आधार पर हत्या करने वालों को समर्थन देना देश से गद्दारी है। सपा द्वारा लगाए गए विवादित पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रेम शुक्ला ने कहा, डॉ. अंबेडकर की आधी तस्वीर के साथ अखिलेश यादव की फोटो लगाना न केवल उनका अपमान है, बल्कि यह दलित समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। भाजपा इस दुस्साहस की निंदा करती है और अखिलेश यादव पर आपराधिक कार्रवाई की मांग करती है।

आउट सोर्सिंग कर्मचारियों ने छटनी के विरोध में प्रदर्शन किया कार्य बहिष्कार, आगे अर्धनग्न प्रदर्शन और कार्यालय घेराव की चेतावनी

सुलतानपुर/ भव्य खबर। विद्युत वितरण मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी बुधवार को कार्य बहिष्कार पर रहे। यहां बिजली कार्यालय पर उन्होंने प्रदर्शन किया। फेस अटेंडेंस और छटनी के खिलाफ वे आंदोलन कर रहे हैं। विरोध का कारण शक्ति भवन के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी फेस अटेंडेंस और छटनी का आदेश है। साथ ही 55 वर्ष की आयु का हवाला देकर कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि निकाले गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। कल तक पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। इसके बाद 2 मई को उपकेंद्र परिचालकों के स्थान पर टीजी 2 को तैनात किया जाएगा। 3 मई को कर्मचारी अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। वहीं 4 मई को कर्मचारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय से दरियापुर तिराहा और बाधमंडी चौराहा होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक मार्च करेंगे। वहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 5 मई को मुख्य अभियंता अयोध्या क्षेत्र के कार्यालय का घेराव करेंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की औद्योगिक अशांति की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों और प्रशासन की होगी। यह जानकारी सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष आनंद अग्रहरि ने दी है।

परशुराम चौक पर भव्य आयोजन के साथ मनाया गया भगवान परशुराम जन्मोत्सव

सुलतानपुर/ भव्य खबर। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव जिले में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर के परशुराम चौक चौराहे पर परशुराम युवा वाहिनी व मिशन परशुराम चौक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हवन पूजन, भव्य शोभायात्रा और विशाल भंडारे की धूम रही। बुधवार सुबह से ही चौराहे को ध्वज-पताकाओं और रंग-बिरंगी सजावट से भव्य रूप दिया गया था। आचार्य पंडित उमानाथ तिवारी के नेतृत्व में पूजा-अर्चना और हवन संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुति दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही भव्य शोभायात्रा, जो परशुराम चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौराहों - बस अड्डा, डाकखाना, शाहगंज, चौक, ठठेरी बाजार व सब्जी मंडी होते हुए पुनः परशुराम चौक पर समाप्त हुई। डीजे की धुनों पर चल रही इस यात्रा में सैकड़ों पैदल और बाइक सवार अनुयाई शामिल रहे। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया।शोभायात्रा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं में सेल्फी का भी खासा क्रेज देखने को मिला। इस आयोजन में विपिन मिश्रा एड-वोकेट, नीरज दुबे एडवोकेट, डॉ. डी.एस. मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आलोक आर्य, संतोष पांडे एडवोकेट, पीसीसी सदस्य योगेश पांडे, अमित कुमार तिवारी, प्रवीण मिश्रा, गिरीश मिश्रा, रमेश सिंह 'टिन्नू भैया', बबिता तिवारी, संगीता शुक्ला, राजेश तिवारी, मोहित तिवारी, अर्जुन पाठक, अंकित श्रीवास्तव सहित सैकड़ों गणमान्य लोग और श्रद्धालु उपस्थित रहे। परशुराम युवा वाहिनी द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्योंजैसे गरीब बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा में सहायता की भी सराहना की गई।

राष्ट्र के निर्माण में मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान: एसएन सिंह

कुशीनगर/ भव्य खबर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर नगरपालिका कुशीनगर क्षेत्र के एमडी सीनियर से-केंडरी स्कूल सपहा में छात्र - छात्राओं ने श्रमिकों से जुड़े पोस्टर प्रदर्शित किया। गुरुवार को मजदूर दिवस पर कार्यक्रम की शुरूआत में छात्र और छात्राओं ने विद्यालय परिसर की सफाई की और सहायक कर्मचारियों, माली और वाहन चालकों को उनके सेवा के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने एक मई मजदूर दिवस के महत्व को बताया कि मजदूर धूप, ठंड, बारिश में बिना रुके कठोर श्रम करता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मजदूरों का समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। हमें इस वर्ग को सम्मान दें। मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने बताया कि मजदूर दिवस की शुरूआत 1886 अमेरिका में हुई। मजदूर का मतलब उनलोगों से है जो लोग नौकरी करते हैं।

गोरखपुर में ओले गिरे, बस्ती में पति-पत्नी की मौत

यूपी में अचानक मौसम बदला, अयोध्या-लखनऊ में आंधी, 30 जिलों में अलर्ट

गोरखपुर। यूपी में गुरुवार को एक बार फिर मौसम अचानक बदल गया। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। 10 मिनट तक ओले भी गिरे। सड़क पर ओले की सफेद चादर बिछ गई। बस्ती में भी तेज आंधी के बाद बारिश और ओले गिरे। यहां भी 10 मिनट तक ओले गिरे। वाल्टरगंज इलाके में बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौत हो गई। अयोध्या में सुबह तेज आंधी आई। यहां दिन में अंधेरा जैसा छा गया। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में भी सुबह से बादल छाए हैं। 20-25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 मई तक प्रदेश के मौसम में इसी तरह उलटफेर होता रहेगा। बारिश के चलते तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट होगी। प्रयागराज में गर्मी और तेज धूप को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इरअ प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि एक से आठवीं तक के स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक रहेंगे। बुधवार की बात करें तो जालौन का उरई सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 41 डिग्री के साथ बांदा और लखीमपुर जिलों का स्थान दूसरा रहा। शाहजहांपुर सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री दर्ज किया गया।

बहराइच और चित्रकूट में 44 किमी की स्पीड से हवाएं चलीं। बस्ती के वाल्टरगंज इलाके में रेहार जंगल गांव में बुधवार को पति-पत्नी पर बिजली गिर गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि रामचरन (55) और उनकी पत्नी चंद्रावती (52) खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। बिजली गिर गई। आसपास के ग्रामीणों ने धुआं उठते देखा और मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने कहा परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया- इस समय दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक शुष्क रेखा मौजूद है, जो केरल तक जा रही है। इसके प्रभाव में पूरा उत्तर प्रदेश आ रहा है। इसके साथ ही एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवाएं और दक्षिण-पश्चिमी हवाएं आपस में टकरा रही हैं। इसी कारण मौसम में यह बदलाव आया है। अयोध्या में मौसम साफ है। सुबह से धूप निकली हुई है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार, शाम तक बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। प्रयागराज में मौसम साफ है। तेज धूप निकली हुई है। सुबह 10 बजे 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया था। गर्मी के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया- अब 8वीं तक के स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे।

मंडप से दूल्हे को अगवा कर ले गई गर्लफ्रेंड

झांसी । बारात जाने से पहले दूल्हे का अपहरण हो गया। ये अपहरण किसी बदमाश या गैंगस्टर ने नहीं, दूल्हे की गर्लफ्रेंड ने किया। वह अपने घरवालों के साथ सीधे दूल्हे के घर पहुंची। हंगामा करते हुए मंडप से दूल्हे को अगवा कर थाने ले गई। बोली- ये प्यार मुझसे करता है और शादी किसी और से करने जा रहा है। थाने में कई घंटे तक पंचायत चली। तब दूल्हा बोला- मैं भी इसी से शादी करना चाहता हूं। वो शादी तोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर चला गया। इसके बाद आनन-फानन में चचेरे भाई को दूल्हा बनाया गया और फिर घरवाले बारात लेकर पहुंचे। इसके बाद शादी संपन्न हो सकी। मामला रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव का है। डेली गांव में रहने वाले सनी की शादी 2 महीने पहले तय हुई थी। शादी के कार्ड बंट चुके थे, सभी रिश्तेदार आ चुके थे। बुधवार शाम रक्सा के ढीमरपुरा गांव में बारात जानी थी। सनी के घर में लगे मंडप में शादी की रस्में चल रही थीं। शगुन के गीत गाए जा रहे थे, दूल्हे सनी को सजाया जा रहा था। तभी दतिया में रहने वाली एक युवती अपने रिश्तेदारों को लेकर वहां आ गई। आते ही उसने हंगामा शुरू कर दिया। बोली- ये शादी नहीं होने दूंगी। सनी मुझसे प्यार करता है। हम दोनों के बीच करीब 10 साल से अफेयर है। मैं सनी को किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करने दूंगी। युवती के हंगामा करने के बाद लड़के वाले भी विरोध में उतर आए। दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगा। इसी बीच युवती ने सनी को जबरदस्ती मंडप से उठा दिया और उसे अपने साथ ले जाने लगी। सनी के घरवालों ने इसका विरोध किया, लेकिन युवती के तेवर के आगे उनकी एक न चली। युवती सनी को लेकर सीधे रक्सा थाने पहुंची। उसके पीछे-पीछे परिवार के लोग भी जा पहुंचे। युवती ने कहा- सनी ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। अब दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। मैं यह नहीं होने दूंगी। सनी अगर दूसरी लड़की से शादी करेगा, तो मैं जान दे दूंगी। इसके बाद थाने में कई घंटे तक पंचायत चली। आखिर में घरवाले सनी से युवती की शादी करने पर राजी हो गए। देर शाम सनी को लेकर युवती दतिया स्थित अपने गांव चली गई। वहीं, ढीमरपुरा गांव में दुल्हन बारात आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका दूल्हा सनी थाने में बैठा था। गर्लफ्रेंड के साथ सनी के जाने की बात तय होने पर घरवालों ने दुल्हन के लिए दूसरा दूल्हा तलाशना शुरू कर दिया। परिवार में ही सनी के चचेरे भाई लकी को दुल्हन को दिखाया गया।

वक्फ सुधार कानून जनजागरण अभियान के अंतर्गत जताया आभार

संवाददाता

कुशीनगर। वक्फ सुधार कानून जनजागरण अभियान के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से गुरुवार को रविन्द्र नगर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड और जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गोंड ने इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आभार जताया ।रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े संशोधन बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने जनजातीय समाज में राहत और विश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए रामकोला विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के कल्याण की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ह्सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासह्व की नीति का एक और उदाहरण इस संशोधन में दिखाई देता है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री गोंड ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में जनजातीय समाज की जमीनों को लेकर जो चिंता रही है, उस पर अब विराम लग चुका है। नए संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब संविधान की 5 वीं और 6 वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की जनजातीय भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा और न ही ऐसा समझा जाएगा। यह प्रावधान सीधे तौर पर देश के करोड़ों जनजातीय समाज के हितों की रक्षा करता है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष कन्हैया गोंड जिला, डॉ केपी गोंड,रामधनी गोंड, राममनोहर गोंड, संजय गोंड, प्रेमचंद गोंड, संजीव गोंड, कुंजबिहारी गोंड, सहदेव गोंड उपस्थित रहे।

कम्युनिस्टों ने मनाया मजदूर दिवस

संवाददाता

कसया, कुशीनगर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (माकपा) द्वारा कसया नगर स्थित तहसील परिसर में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। वक्ताओं ने एक मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की मांग की। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में मजदूरों और पार्टीजनों को संबोधित करते हुए जिला सचिव कामरेड अयोध्या लाल श्रीवास्तव ने कहा कि जब पूरी दुनिया में कारखानों और संस्थानों मजदूरों से 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था। तब सोने, आराम करने और अन्य काम के लिए समय नहीं मिलता था। जिसके विरुद्ध दुनिया के मजदूरों ने क्रांति की। अमेरिका के शिकागो में एक मई 1886 को 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे अन्य काम की मांग को लेकर लाखों मजदूरों ने आंदोलन किया। मिल मालिकों और सरकार की गोलियों से सैकड़ों मजदूर मारे गए। अंत में मजदूरों की जीत हुई और काम के आठ घंटे तय हुए। आज सरकार मजदूर हितों का दमन कर रही है। उनके अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है। जिसके विरोध में देश के मजदूर संगठनों ने 20 मई को पूरे देश में आंदोलन का निर्णय लिया है। इस दौरान मुहम्मद इदरीश, बीपी गुप्ता, गेंदा सिंह, जवाहर शर्मा, कैलाश गिरी, राजेंद्र सिंह, शंकर प्रसाद, हरि किशुन, केदार सिंह, डा. राघवेंद्र सिंह, हसमुद्दीन, अक्षयबर पासवान, राजू, बिकाऊ, शम्भु नाथ सिंह, गोरखनाथ सिंह, राम किशुन, लालबिहारी, सीताराम मौर्या, भंते रत्नाकर आदि सहित मजदूर मौजूद रहे।

राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों की भांति निजी संस्थानों को भी एसआईआरएफ रैंकिंग में सम्मिलित किया जाए: मुख्यमंत्री

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप युवाओं को तैयार करने हेतु तकनीकी शिक्षा में सतत सुधार अनिवार्य: मुख्यमंत्री

लखनऊ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में नवाचारों के समावेश एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि विगत आठ वर्षों में तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, नवाचारपरक एवं परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक ठोस पहलें की गई हैं, जिनके उत्साहवर्धक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सभी प्राविधिक संस्थान नैक, एनबीए तथा एनआईआरएफ मूल्यांकन में प्रतिभाग करें, परंतु आवेदन से पूर्व व्यापक तैयारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों की रैंकिंग की सराहना करते हुए इसके अंतर्गत निजी संस्थानों को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिए, ताकि समस्त संस्थानों में गुणवत्ता की समान मानक सुनिश्चित हो सकें। मुख्यमंत्री जी शुक्रवार को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल तथा व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्ष 2024-25 हेतु कुल 1.64 लाख सीटों पर नामांकन हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें टडडउ आधारित अध्ययन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट तथा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सम्मिलित किए गए हैं। सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय के 12,739 छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ, जिसमें अधिकतम वार्षिक वेतन ड्59.91 लाख रहा। इसी प्रकार, एमएमएमयूटी, गोरखपुर में वर्ष 2023-24 में छात्रों को ड्52 लाख वार्षिक वेतन तक के पैकेज पर प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट मिला। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में व्यवहारिक अध्ययन को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए तथा गुणवत्तापूर्ण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक श्रेणी के सभी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि नवस्थापित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, गोंडा, मीरजापुर एवं प्रतापगढ़ के भवन निर्माण तथा परिसर विकास से जुड़ी सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण की जाएं, ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से यह कॉलेज अपने निजी परिसरों से संचालित हो सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत करते समय स्थानीय औद्योगिक आवश्यकताओं एवं संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाए। तकनीकी शिक्षा के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 2139 पॉलीटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 147 राजकीय, 18 पीपीपी मोड, 19 अनुदानित एवं 1948 निजी संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों में 2.68 लाख से अधिक प्रवेश क्षमता उपलब्ध है, जिनमें 1.15 लाख से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। विभाग द्वारा डिजिटल कक्षाएं, आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति, उद्योग-संलग्न पाठ्यक्रम, तथा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एवं मशीन लर्निंग को पाठ्यक्रमों में समाहित किया गया है। वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में 39 नए राजकीय पॉलीटेक्निक स्थापित किए गए हैं तथा 13,000 से अधिक शिक्षकों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 324 राजकीय एवं 2982 निजी आईटीआई प्रदेश में संचालित हैं। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से 212 राजकीय आईटीआई को आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं कुशल प्रशिक्षकों से सुसज्जित कर उन्नत बनाया गया है। इन संस्थानों में दीर्घकालिक ट्रेड्स के साथ-साथ स्वल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में लगभग 1.25 लाख प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 30,000 से अधिक छात्रों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि सीएसआर फंड के माध्यम से राज्य के 37 से अधिक जनपदों में प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों द्वारा आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही, मासिक प्लेसमेंट डे के आयोजन से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में सफलता मिली है। एनपीएस और सीएमएपीएस योजनाओं के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में 2.67 लाख से अधिक अप्रेंटिस नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को उद्योगों से और अधिक गहराई से जोड़ा जाए तथा प्रत्येक छात्र को प्रशिक्षण के साथ एक निश्चित अवधि की औद्योगिक इंटर्नशिप सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा केवल प्रमाण-पत्र प्राप्ति का

माध्यम न होकर एक व्यवहारिक, कौशलपूर्ण एवं उपयोगी प्रणाली होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक युवा को उसके कौशल के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

जाति जनगणना का बिहार चुनाव पर क्या पड़ेगा असर?

एक फैसले से राहुल-तेजस्वी चित, आरक्षण विरोधी का दाग धोया!, 4 पॉइंट में जाति का सियासी गणित

पटना। 'आजादी के बाद से जनगणना में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा जाति आधारित गणना नहीं की है। जातीय जनगणना कराने का कोई एजेंडा नहीं है।' 'राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को अगली जनगणना में शामिल किया जाएगा। सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 1947 से जाति जनगणना नहीं हुई है।' महज 4 साल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया है। पहले जाति जनगणना नहीं कराने पर अड़ी सरकार ने अब कराने का ऐलान किया है। हालांकि, जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में एक साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरूआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार चुनाव में माइलेज लेने के लिए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है? क्या विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की ये एक प्लानिंग है? बिहार विधानसभा चुनाव में 5 महीने बाकी है। बड़ी विपक्षी पार्टियां RJD-कांग्रेस जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रही थी।

भाजपा पर आरक्षण विरोधी का तमगा लगता रहा है, लेकिन इस दांव से उसने इसको उलटने का प्रयास किया है। साथ ही विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे को खत्म करने का प्रयास किया है। सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन कहते हैं, ह्यबिहार चुनाव एक बड़ा इश्यूज है। इससे बीजेपी को बिहार चुनाव में नफा ही होगा। एक दाव से उसने बड़े विपक्षी एजेंडे को समाप्त कर दिया। अब उन्हें दूसरा मुद्दा ढूढ़ना पड़ेगा। अब वे बस क्लेम कर सकते हैं कि हमने मुद्दा उठाया। सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल कहते हैं, BJP अब धर्म से हटकर जाति की पिच पर खेलना चाहती है। इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। वहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट अरुण पांडेय कहते हैं, ह्यऐसी योजनाओं का लाभ उसे ही मिलता है, जो इसकी घोषणा करता है। मंडल कमीशन का गठन कांग्रेस ने किया, लेकिन इसका लाभ वीपी सिंह को मिला। क्योंकि लागू उन्होंने ही कराया था। जनवरी से अब तक बिहार दौरे पर 3 बार आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना के वादे करते

रहे हैं। उन्होंने तो बिहार के जातीय सर्वे को फेक करार भी दिया था। उनकी एक मांग ये भी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको उतनी भागीदारी। केवल राहुल गांधी ही नहीं बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इसे पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। विपक्ष के पास अगला ऑप्शन क्या है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई कहते हैं, ह्यविपक्ष केवल जनगणना तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की मांग है कि जिसकी जितनी संख्या है, उसकी उतनी भागीदारी हो। बीजेपी को लाभ- बिहार में भाजपा का आधार वोट सवर्ण और बनिया को माना जाता है। नीतीश कुमार जैसे सहयोगी उसके पास हैं, जो अतिपिछड़ा वोटबैंक को साधते हैं। जाति जनगणना का सबसे ज्यादा लाभ अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) को हो सकता है। EBC में भाजपा ने हाल के दिनों में अपनी पैठ बनाया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट अरविंद मोहन कहते हैं, इस फैसले से पिछड़े और EBC में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसका फायदा चुनाव में दिख सकता है। क्योंकि ये जातियां लालू यादव से छिटकने के बाद अब तक नहीं जुड़ पाई हैं। अरुण पांडेय कहते हैं, BJP पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा था कि वो सवर्ण को साधने के लिए पिछड़ों को इग्नोर कर रही है। जबकि, इखढ सवर्ण-पिछड़ों की राजनीति करती रही है। मौजूदा समय में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रूप में इखढ की लीडरशीप पिछड़े के हाथ में ही है। BJP को नुकसान- पॉलिटिकल एनालिस्ट राशिद किदवई कहते हैं, ह्यइस फैसले के बाद अब इखढ के ऊपर आरक्षण की जो सीमा 50 फीसदी निर्धारित की गई है, उसे हटाने का दबाव बढ़ेगा। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देनी होगी। ऐसे में सवर्ण जो मौजूदा समय में इखढ के साथ हैं, वे इखढ का विरोध कर सकते हैं। यही कारण है कि इखढ कभी भी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात नहीं करती है। अरुण कुमार पांडेय कहते हैं, बिहार में जातीय सर्वे कराना का क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। उनके कार्यकाल में ही सर्वे हुआ। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी उन्होंने उठाया। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी खउब को 18.9 फीसदी वोट मिला। पार्टी का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा। 16 में से 12 कैंडिडेट चुनाव जीतने में सफल रहे थे। लोकसभा के ट्रेंड को अगर विधानसभा में कन्वर्ट करें तो 15 साल बाद JDU एक बार फिर से बिहार विधानसभा में सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर सकती है। 243 विधानसभा सीटों में से 74 सीटों पर JDU आगे थी। अरुण पांडेय कहते हैं, केंद्र के जातीय जनगणना के पूरा होने में अभी दो साल लगेंगे। इसी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन होना है। महिला का आरक्षण तय होना है। इसी के आधार पर 2029 का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और NDA सरकार को इसका लाभ होना तय माना जा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार ने विपक्ष के इस मुद्दे को चुनाव से ही खत्म कर दिया। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति काफी मायने रखती है, वहां अब विपक्ष को नया मुद्दा तलाशना होगा। हालांकि, चुनाव में अभी काफी वक्त है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।

'पत्नी साथ नहीं रहती, इसलिए साले को मार डाला'

दरभंगा। पुलिस ने विकास हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बहनोई ने गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के बाद वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा था। आरोपी हरिचंद्र राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जाले के जोगियारा गांव में 23 अप्रैल को विकास का शव मिला था। एसडीपीओ ज्योति कुमारी ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस की पूछताछ में हरिचंद्र ने बताया कि 9 साल पहले विकास की बहन गीता देवी से इंटरकास्ट मैरिज किया था। 8 साल का एक बेटा भी है। पहले हमलोग दिल्ली में रहते थे। कुछ महीनों से पत्नी साथ नहीं रहती है। ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे। इसको लेकर दिल्ली के करोलबाग

थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मानसिक तनाव में आकर 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका हूं। पुलिस के मुताबिक पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने विकास का चेहरा जला दिया था। पूरे शरीर पर चाकू से कई वार किए। हत्या के बाद वीडियो बनाकर पत्नी के मोबाइल पर भेज दिया। चाकू को जंगल में फेंक दिया था। विकास का शव गांव के बाहर बगीचे से मिला था।

भीड़ ने युवक की पीट-पीटकर की हत्या

दोस्त की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस

मधुबनी। ग्रामीणों ने पीट-पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। घटना राजनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर बलाट गांव की है। मृतक की पहचान मधुबनी गिलेशन बाजार निवासी बिरजू शाह के पुत्र नंद किशोर शाह (25) के रूप में की गई है।

घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि मधुबनी नीलम चौक निवासी प्रेम कुमार ,शक्ति झा सहित कुछ दोस्तों के साथ रात्रि में राघोपुर बलाट गांव गया था, जहां उनकी वहां के कुछ युवकों से झड़प हो गई। इस घटना में प्रेम कुमार का सिर फट गया, जिसके बाद उसके बाद मधुबनी शहर से कुछ युवक के साथ नंदकुमार तकरीबन 12 बजे

के आसपास गांव में घटना की जानकारी लेने के लिए गया था। इसी बीच गांव के लोगों को लगा कि यह लोग फिर मारपीट करने आया है। इसी बात को लेकर भीड़ ने उन लड़कों पर हमला कर दिया। इस हमले में नंद कुमार मोटा होने के कारण भाग नहीं सका, जिस वजह से ग्रामीणों ने नंद किशोर शाह की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर स्थिति होने पर लोगों ने गंभीर रूप से घायल नंदकिशोर शाह को सड़क के किनारे पफेंक कर फरार हो गये। इस बात की सूचना किसी ने राजनगर थाना अध्यक्ष विकास कुमार को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल नन्द कुमार को राजनगर पीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नंद किशोर शाह की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन उसके शव को लेकर सड़क जाम कर दिया। हंगामा और सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और फिर परिजनों को काफी समझाने के बाद जाम को हटाया जा सका। फिर शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राजनगर थाना की पुलिस मृतक के घायल दोस्त प्रेम कुमार और उनके अन्य दोस्तों के बयान पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है।

संक्षिप्त डायरी

बिहार में महिला खिलाड़ियों के लिए नई शुरूआत

पटना/ भव्य खबर/ बाबुल श्रीवास्तव । बिहार के खेल जगत में इन दिनों एक अनोखी क्रांति देखने को मिल रही है। जहां पहले खेल के मैदान में सिर्फ जीत-हार की चर्चा होती थी, वहीं अब महिला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और खासकर

माहवारी जैसे विषयों पर खुलकर बात हो रही है। इसकी वजह है सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशन और बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की साझेदारी, जिसने जमीनी स्तर पर महिला खिलाड़ियों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठाया है। 2023 में शुरू हुई इस पहल के तहत पटना, सिवान और दरभंगा जैसे जिलों में वर्कशॉप्स आयोजित की गईं। इन वर्कशॉप्स में 15 साल की उम्र से लेकर अलग-अलग खेलों की लड़कियों ने हिस्सा लिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि ज्यादातर लड़कियां सैनिटरी पैड्स तो इस्तेमाल करती थीं, लेकिन खून की कमी (हीमोग्लोबिन) या पीसीओएस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। दर्द और थकान आम थी, लेकिन सही सलाह या इलाज तक पहुंच बहुत कम थी। 2024 में जब कोच और खिलाड़ियों के लिए खास ट्रेनिंग रखी गई, तो माहवारी को लेकर बातचीत में बदलाव दिखा। पहले जहां 'पर्सनल प्रॉब्लम' जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, वहीं अब खिलाड़ी खुलकर अपनी बात रखने लगीं। कोचों को भी बताया गया कि माहवारी के दौरान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैसे बदली जा सकती है। पोषण संबंधी सर्वे में पता चला कि ज्यादातर लड़कियां दिन में तीन बार खाना तो खाती हैं, लेकिन प्रोटीन और जरूरी विटामिन की कमी है, जो उनके खेल और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। इस साल एक नया कदम उठाया गया-ह्यसिंपली बेरीह्न नाम का व्हाट्सएप आधारित पीरियड ट्रैकर। अब खिलाड़ी अपनी माहवारी और उससे जुड़े लक्षणों को आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। इससे न सिर्फ उनकी जागरूकता बढ़ी है, बल्कि कोचिंग और ट्रेनिंग भी ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से हो रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार ह्यसिंपली पीरियड्सह्न कियोस्क लगाया जा रहा है। यहां खिलाड़ी अलग-अलग पीरियड प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल कर समझ सकती हैं, माहवारी और खेल पर खुलकर चर्चा कर सकती हैं, और मुफ्त पीरियड केयर किट्स भी पा सकती हैं। कोच और माता-पिता के लिए भी छोटे-छोटे सेमिनार होंगे, ताकि वे भी इस विषय को बेहतर समझ सकें। बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की यह पहल सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। जब लड़कियों को अपने शरीर और सेहत की सही जानकारी मिलेगी, तो वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। साथ ही, कोच और अभिभावक भी उन्हें बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे। यह साझेदारी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। अब बिहार की बेटियां न सिर्फ मैदान में, बल्कि अपने स्वास्थ्य के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। खेलो इंडिया 2025 में बिहार सिर्फ पदक जीतने नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल पेश करने जा रहा है। माहवारी पर खुली बातचीत, आत्मविश्वास से भरी मुस्कानें और हर लड़की के लिए बराबरी का मौका- यही है असली जीत। बिहार की यह पहल दिखाती है कि जब सेहत और खेल एक साथ चलते हैं, तो असली बदलाव आता है। उम्मीद है, यह कहानी देशभर में नई सोच और नई शुरूआत की प्रेरणा बनेगी।

मिथिला और मगध संस्कृति को एक करने के लिए निकाली 70 किमी लंबी यात्रा

बेगूसराय। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर जयमंगलागढ़ से मोकामा तक जयमंगला वाहिनी ने 70 किमी लंबी धर्मयात्रा निकाली। यह यात्रा बेगूसराय जिले के जयमंगलागढ़ से शुरू होकर पटना के मोकामा स्थित भगवान परशुराम के मंदिर तक गई। यात्रा की शुरूआत से पूर्व माता जयमंगला के मंदिर में जयमंगला वाहिनी के सदस्यों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद सदस्यों के बीच प्रसाद का वितरण किया। ध्वज, डीजे और शंखनाद के साथ यात्रा की शुरूआत जयमंगलागढ़ मंदिर परिसर से हुई।इस दौरान जय मां जयमंगला, जय भगवान परशुराम, जय श्रीराम और जय हनुमान के नारों से संपूर्ण वातावरण गुंजयमान होता रहा। यात्रा में जयमंगला वाहिनी के दर्जनों कार्यकताओं के साथ सैंकड़ों सनातनियों ने इस धर्म

यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा बीते कई साल से निकाली जा रही है। इस अवसर पर जयमंगला वाहिनी से जुड़े हुए शुभम कुमार, जेपी कुमार, सिंह मालिक, सोनू कुमार, गोपाल झा, सुंदरम वत्स, भानु कुमार आदि लोगों ने कहा कि यह आठवां साल यात्रा का है। हम लोगों को धर्म जागरण के लिए काम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इससे हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं।बिहार के अंदर सबसे लंबी धाम यात्रा है, जो बेगूसराय के जयमंगलागढ़ से पटना के मोकामा परशुराम मंदिर तक जाती है। रास्ते में सभी सनातनियों का भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहता है। इस अवसर पर जदयू नेता संजय सिंह, आरसीएस कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतांशु कुमार, कोषाध्यक्ष सत्यम कुमार, रोहित कुमार, अभिषेक सिंह, भाजपा नेता शालिग्राम सिंह, जयप्रकाश सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।यात्रा जयमंगलागढ़ से पूजा कर प्रारंभ हुई। यह मंझौल, राजौरा, मोहनपुर, पन्हास, हर हर महादेव चौक, जीरोमाइल, बीहट बड़ी दुर्गा मंदिर, सिमरिया, हाथीदह होते हुए मोकामा के बाबा परशुराम मंदिर पहुंच कर संपन्न हुई। संयोजक अवनीश कुमार उर्फ सिंह मालिक और शिवम ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य मिथिला और मगध की संस्कृति को जोड़ना है। उन्होंने बाबा परशुराम का आशीर्वाद लेकर राष्ट्र के विकास की कामना की। वहीं, अमन और सोनू कुमार ने बताया कि भगवान परशुराम की जयंती हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। परशुराम का जन्म न्याय और धर्म की रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भक्तगण उनसे शक्ति, साहस और बुराई से सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं।

डीएलएड की छात्रा ने फंदे लटक कर दे दी जान

सीवान। डीएलएड की एक छात्रा का शव फंदे से लटकता हुआ मिला' आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी ' सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई ' घटना महादेवा थाना क्षेत्र के मालवीय नगर स्थित नई बस्ती की है ' मृतका की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र के चित्तौड़िया गांव निवासी दाहुड़ राय का 20 वर्षीय पुत्री सुधा कुमारी है' घटना के संबंध में मृतक के चाचा ने बताया कि सुधा सीवान में रहकर डाएट में डीएलएड की पढ़ाई करती थी' साथ ही वहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी' मंगलवार की रात्रि 8:00 बजे परिजन सुधा के मोबाइल पर कॉल कर रहे थे, लेकिन मोबाइल लगातार बंद आ रहा था' इसके बाद पुनः सुबह में कॉल किया गया, लेकिन उस समय भी उसी तरह मोबाइल बंद था ' फिर दोपहर में मकान मालिक ने परिजनों को फोन पर बताया कि सुधा का दरवाजा

अंदर से बंद है ' कई बार आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है ' फिर परिजन सीवान पहुंचे तो देखा कि उसे पुलिस शव को बेड रखा है ' उन्होंने यह भी बताया कि सुधा तकरीबन डेढ़ वर्षों से सजवान में रहकर पढ़ाई करती थी ' परिजनों का कहना है कि मुताबिक सुधा दुपट्टा के सहारे पंखे से लटकी हुई थी' जब हम लोग वहां पहुंचे तो पंखे में भी फंदा था और उसके गले में भी फंदा पाया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि सुधा ने आत्महत्या की है ' हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है' घटना के संबंध में थानाध्यक्ष निर्भय कुमार ने बताया कि फंदे से लटक कर एक युवती ने आत्महत्या की है' मामले की जांच की जा रही है'

वक्फ कानून के खिलाफ ब्लैकआउट

विरोध करने पर मिली धमकी

मुंगेर। वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में बुधवार रात आयोजित ब्लैकआउट के दौरान मुंगेर में तनाव की स्थिति बन गई। ब्लैकआउट का विरोध करने पर सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार को कुछ उपद्रवियों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। डॉ. सुधीर ने सुभाष नगर स्थित अपने मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट बंद करने का विरोध किया था। ब्लैकआउट का आह्वान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत-ए-शरिया बिहार, झारखंड, ओडिशा के अमीर-ए-शरीयत मौलाना फैसल रहमानी के द्वारा किया गया था। इसके तहत बुधवार रात 9 बजे से 9:15 बजे तक सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से लाइट बंद करने की अपील की गई थी। इसी दौरान सुभाष नगर स्थित हिंदू मोहल्ले में कुछ युवक पहुंचे और पोल पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद करने

लगे। जब डॉ. सुधीर कुमार ने इसका विरोध किया, तो युवकों ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी और वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने को कहा। मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। घटना के बाद भाजपा विधायक प्रणव कुमार यादव डॉक्टर के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध का अधिकार है। किसी नागरिक को धमकाना और डराना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसपी से बात की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ तत्वों ने बिजली विभाग को गलत सूचना देकर शहर की विद्युत आपूर्ति को बाधित करने की साजिश रची थी, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

तेजस्वी यादव ने खुद छोड़े पटाखे

बोलेः आखिर हम जीते, यह हमारे पुरखों की जीत

पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में जातीय जनगणना करने का एलान किया है। यह घोषणा होते ही इस पर राजनीति सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसका श्रेय लेने की होड़ में लग गये हैं। इस संबंध में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वह काफी चर्चा में है। उन्होंने इसको लालू प्रसाद की, समाजवादियों की, उनकी और उनके पुरखों की जीत बताया है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जातीय जनगणना कराकर आरक्षण 65 फीसदी बढ़ाए थे। जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, तब हमने कैबिनेट में केंद्र सरकार को यह सिफारिश भी भेजी थी ताकि उसको अनुसूची 9 में डाला जा सके। लेकिन अब तक भारत

सरकार ने यह काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने कोर्ट में इस मामले को फंसाया। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह हमारी मांग है, यह हमारी ही जीत है। यह लालू जी की जीत है, यह हमारे पुरखों की जीत है। यह समाजवादियों की जीत है। यह हमारे ही एजेंडे की बात कर रही है जो भाजपा कल तक कहती थी नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की ताकत है। तेजस्वी यादव ने मांग करते हुए कहा कि यह परिसीमन से पहले होना चाहिए। पिछड़े और अति पिछड़ों का पार्लियामेंट में विधानसभा के चुनाव में सीटों को आरक्षित करना होगा जिस प्रकार से दलित भाइयों का है और आदिवासी भाइयों का है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि- 'मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने, स्व. मुलायम सिंह, स्व. शरद यादव ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप्प किया और बाद में प्रधानमंत्री स्व० मनमोहन सिंह के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ। जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जातिगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते है उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते है। जातिगत जनगणना की माँग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है। हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे।'

संक्षिप्त डायरी

करनाल का 22 वर्षीय युवक 4 साल पहले गया था अमेरिका, अब परिवार पर टूटा दुःखों का पहाड़

करनाल/ भव्य खबर। करनाल के सौंकड़ा गांव में रहने वाले 22 वर्षीय सुखबीर सिंह की अमेरिका में हादसे में मौत हो गई। यह हादसा ट्रक चलाते समय हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। बहन की कुछ महीने पहले शादी हुई थी। इंग्लैंड से आई बहन की हालत बेहद गंभीर है। ट्रक के डीजल टैंक में लगी आग मृतक के ताया राजेंद्र सिह ने बताया कि सुखबीर कल शाम को परिवार से बात कर रहा था। जहां पर यार्ड में ट्रक खड़ा करना था, कुछ देर बाद वहां पहुंचने वाला था। उसने अपने पिता को कहा कि मैं घर पहुंचकर बात करता हूं। 30 मिनट बाद हादसे के बारे में परिवार के पास फोन आ गया। मृतक सुखबीर चार साल पहले अमेरिका गया था। हादसे के समय सुखबीर ट्रक में सामान लोड करके जा रहा था। ताया ने बताया कि हमारे पास अभी जीतनी जानकारी है उसके अनुसार ट्रक पहले डिवाइडर से टकराया और ट्रक के डीजल टैंक फट गया और उसमें आग लग गई। सुखबीर ने कोशिश भी की बाहर निकलने की। पर वह बाहर निकल नहीं पाया। मृतक के चाचा ने बताया कि सुखबीर डोंकी रूट से अमेरिका गया था। मृतक के परिवार के कुछ लोग विदेश में थे। सुखबीर का भी विदेश जाने का मन था। अब परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। चाचा ने कि अभी 3 महीने पहले इंग्लैंड में बहन की शादी की थी। घर में बहुत खुशी थी। परिवार में सुखबीर की दो बहनें हैं। हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है।

हिसार में 10 दिन का पानी शेष, टैंकर सप्लाई भी बंद, लोगों मे मचा हाहाकार

हिसार/ भव्य खबर। हिसार में एक तरफ में गर्मी ने कहर ढा रखा है। दूसरी ओर पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, शहर के जलघरों में सिर्फ 10 दिन का पानी बचा है, जिससे लोगों का पानी का संकट सताने लगा है। इसके अलावा नहरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। बालसमंद ब्रांच से भाखड़ा नहर का प्रवाह रुकने के बाद अब नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास पानी बचाने और बांटने की चुनौती है। एक दिन छोड़ कर होगी पानी की सप्लाई पब्लिक हेल्थ विभाग ने ऐलान किया है कि शहर में अब एक दिन छोड़ कर पानी की सप्लाई की जाएगी। साथ में ये भी कहा कि उस दिन सिर्फ एक बार ही पानी आएगा। जल संकट के इस दौर में कई कॉलोनियों और सेक्टरों में हाहाकार मच गया है। वहीं, दूसरी ओर ल्तरश्ढकी ओर से नियुक्त टैंकर ठेकेदार ने भुगतान न मिलने के चलते सप्लाई रोक दी है। हर दिन लगभग 150 घरों में पानी पहुंचाने वाला ठेकेदार अब अपने 20 लाख रुपये के बकाया बिल को लेकर खफा है। ठेकेदार को पैसे न मिलने के कारण टैंकर सेवा ठप हो चुकी है। इसके चलते लोगों में रोष पनप रहा है। पुराने शहर के कुछ हिस्सों में यह मात्रा महज 4 से 5 दिन का पानी बचा है, जिसके कारण लोगों पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसेंगे। मेयर ने बुलाई आपात बैठक उधर, पानी की सप्लाई न होने के कारण गुरुवार को नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली ने डीसी और संबंधित विभागों की आपात बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में जल संकट से निपटने के लिए जरूरी रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

दर्दनाक हादसा,काम कर सोए मिस्त्री की जलने से मौत जलकर हुआ राख

जींद/ भव्य खबर। जींद के सफीदों रोड स्थित ऑटो मार्केट में बुधवार रात दर्दनाक हादसे में एक मिस्त्री की जलने से मौत हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सफीदों रोड पर जॉइंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ आगे बनी ऑटो मार्केट की एक दुकान में काम करने वाला 46 वर्षीय राजेश नामक मिस्त्री बुधवार को दुकान का काम निपटाने के बाद रात को दुकान के ऊपर बने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब दुकान का मालिक ईश्वर मार्केट में पहुंचा और ऊपर कमरे में मिस्त्री को उठाने गया, तो सब कुछ जला हुआ था। दुकान के ऊपर का पूरा कमरा जलकर राख हो चुका था और उसमें सोए राजेश मिस्त्री की भी जल जाने से मौत हो चुकी थी। दुकान मालिक ईश्वर ने इस्की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी। बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस को भी इस हादसे की सूचना दी गई। दुकान मालिक ईश्वर के अनुसार मिस्त्री राजेश को वह रात 10ः बजे काम निपटाने के बाद दुकान पर छोड़कर चला गया था और राजेश दुकान के ऊपर बने कमरे में जाकर सो गया था। आग किस कारण से लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में जान गंवाने वाला मिस्त्री राजेश मूल रूप से रोहतक जिले के किलोई गांव का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से वह जींद के भिवानी रोड की बूढ़ा बाबा बस्ती में रह रहा था।

हांसी में युवक पर दनादन फायरिंग बाइक पर सवार होकर आए थे हमलावर

हांसी / भव्य खबर। हांसी के गांव सैनीपुरा में फायरिंग का मामला सामने आया है। तीन हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने युवक पर फायरिंग की। घायल युवक को हांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुकाबिक गांव सिसाय के रहने वाला जयदीप अपने दो साथियों के साथ हांसी की तरफ आ रहा था। अभी ढाणी पाल मोड़ के पास से बाइक पर आए तीन युवकों ने उन पर गोलियां चला दी। हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे। जिस कारण उनकी पहचान नहीं हो पाई।

हरियाणा पहुंचेगा 8500 क्यूसेक पानी, BBMB ने पंजाब कोटे के डायरेक्टर आकाशदीप को हटाया

विवाद के बीच नंगल छावनी में बदला

पंचकूला। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे भाखड़ा नहर से पानी के विवाद के बीच बीबीएमबी ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) ने भाखड़ा डैम के डायरेक्टर (वाटर रेगुलेशन) इंजीनियर आकाशदीप सिंह को हटा दिया है। वह पंजाब के कोटे से इटइ में तैनात थे। जिसका पंजाब सरकार ने कड़ा विरोध किया है। आकाशदीप की जगह अब इंजीनियर संजीव कुमार को डायरेक्टर रेगुलेशन लगाया गया है। संजीव हरियाणा के कोटे से पद पर आकाशदीप को नियुक्त कर दिया गया है। ऑर्डर में दावा किया गया है कि यह फैसला आकाशदीप की ही बोर्ड में नियुक्त हैं। संजीव इससे पहले डैम सेफ्टी के डायरेक्टर थे। उनकी जगह पर इस डैम सेफ्टी के डायरेक्टर मांग पर किया गया है। पंजाब सरकार ने किया विरोध वहीं, पंजाब सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने BBMB को लिखा कि संजीव कुमार को सिर्फ डेम सेफ्टी का अनुभव है। वाटर रेगुलेशन को लेकर उनके पास कोई अनुभव नहीं है, इसलिए इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। हालात देख पंजाब सरकार ने नंगल डैम की सुरक्षा बढ़ा दी है। यहां DIG की अगुआई में पुलिस तैनात कर दी गई है। हरियाणा को ज्यादा पानी देने से रोकने के लिए सरकार और भी कदम उठा सकती है। आकाशदीप सिंह भाखड़ा बांध के इंजीनियर हैं जिनका काम तीनों राज्यों की अनुमति के बाद पानी छोड़ने का है, उन्होंने कल बीबीएमबी की बैठक में पंजाब की अनुमति के बिना पानी छोड़ने से मना कर दिया था। आकाशदीप सिंह पंजाब कैडर के इंजीनियर हैं और इस समय बीबीएमबी में डेपुटेशन पर है। हरियाणा को मिलेगा 8500 क्यूसेक पानी वहीं हरियाणा के लिए 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला बुधवार शाम भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति की पांच घंटे लंबी बैठक में लिया गया। बीबीएमबी भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर बांधों से पानी के वितरण को नियंत्रित करता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान साझेदार राज्य हैं जो सिंचाई सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी आवश्यकताओं को भाखड़ा और पोंग बांधों से पूरा करते हैं। सूत्रों ने बताया कि बीबीएमबी की बैठक के दौरान पंजाब सरकार के अधिकारियों ने हरियाणा को अधिक पानी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और दावा किया कि पड़ोसी राज्य ने पहले ही अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर लिया है। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने यह भी तर्क दिया कि पौंग और रंजीत सागर बांधों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले कम है। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान भाजपा शासित राजस्थान के अधिकारियों ने भी हरियाणा की मांग का समर्थन किया। बीबीएमबी के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मान ने गुरुवार को हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी दिए जाने के कदम का कड़ा विरोध किया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात पंजाब के इंजीनियर और विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार बैठक में अपना विरोध दर्ज करवाकर बैठक को बीच में छोड़कर चले आए। आज जबकि नंगल वाटर कंट्रोलिंग से पानी को छोड़ें जाना है वहां पर भारी गिनती में पुलिस तैनात कर दी गई है। कहा जा रहा है कि यह पहलगाम हमले के बाद डैम की सुरक्षा को लेकर बढ़ाई गई है लेकिन सूत्रों का कहना है कि पंजाब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर दम से पानी रिलीज नहीं किया जाएगा।

पानीपत में BJP नेता की गुंडागर्दी निगम के खए की सरेआम की पिटाई

पानीपत : पानीपत में भाजपा नेता की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां भाजपा नेता ने निगम के जेई को सरेआम पीटा। मोंटी राणा बिचपड़ी मंडल से युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है। यह मामला पानीपत की खादी कॉलोनी का बताया जा रहा है। पीड़ित जेई अरुण राणा ने मॉडल टाउन थाने में शिकायत दे दी है। मारपीट की वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित जेई अरुण राणा के भाई ने ही आपसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिलवाया है। पीड़ित जेई ने पुलिस में शिकायत दे दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

होडल पहुंचे सीएम सैनी ने खोला सौगातों का पिटारा करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन

हरियाणा : सीएम सैनी ने बीते दिन बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर पलवल पहुंचे थे। यहां सीएम ने जिले के होडल विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं की सौगात दी। होडल विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने 10 करोड़ रुपए की लागत से बने नगर पालिका भवन, उप तहसील भवन और खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने होडल में 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने बताया कि बृज की यह भूमि वीरता और संस्कारों की धरोहर है।

होडल के विधायक हरिंद्र सिंह रामरत ने विधानसभा क्षेत्र के लिए 152 मांगें रखीं। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा अपने चुनावी संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया के शुभ और पुण्य पर्व पर आप सबके बीच आकर मन अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने इस पावन पर्व की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बृज भूमि होडल में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। होडल का नाम जब भी लिया जाता है, हमारे मन में एक ऐसा चित्र उभरता है, जहां की मिट्टी में मेहनत, वीरता की गाथाएं और संस्कारों की खुशबू विद्यमान है। वहीं मुख्यमंत्री ने पलवल जिला के विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अपने पिछले दो कार्यकालों में जिला पलवल को विकसित करने के लिए कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2,345 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया।

यमुनानगर में गंदे पानी से फैली बीमारी, बुखार के 78 संदिग्ध मामले आए सामने, बना चिंता का माहौल

यमुनानगर : यमुनानगर के तेजली गांव में चारों तरफ गंदगी है, नालियां ओवरफ्लो हैं। सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पीने के पानी की लाइन नालियों के साथ-साथ गुजर रही हैं। जानकारी मिलते ही यमुनानगर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 29 अप्रैल को एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) गांव में भेजी। पिछले दो दिनों में टीम ने 380 घरों का सर्वे किया। जिनमें से 26 पुरुषों व 52 महिलाओं में बुखार के लक्षण पाए गए। इलाका वासियों का कहना है कि लंबे समय से सीवरेज लाइन बिछी हुई है, वह खराब हो चुकी है। यहां के अधिकतर लोगों को बुखार उल्टी और पेट दर्द की शिकायत है। रिपोर्ट में टाइफाइड सहित अन्य कारण नजर आ रहे हैं। कुछ इलाके में लीकेज का पता चला, उसे मरम्मत करके ठीक भी किया गया है। प्रभावित ग्रामीणों को पिछले एक सप्ताह से तेज बुखार, सिर दर्द और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। बताया गया है कि RRT ने हेपेटाइटिस A, B, C और E,

टाइफाइड (विडाल टेस्ट), लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टायफस की जांच के लिए 40-40 खून के नमूने एकत्र किए हैं। सभी सैंपल प्रयोगशाला में बैक्टीरियोलॉजिकल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रारंभिक जांच में पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में दो स्थानों पर रिसाव पाया गया। कल विभिन्न घरों से लिए गए 11 पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए। आज फिर 11 और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।यमुनानगर के तेजली गांव में चारों तरफ गंदगी है, नालियां ओवरफ्लो हैं। सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है।

सरकार का बड़ा कदम, फैमिली ID में गलतियों को सही करने के लिए स्कूल के छात्रों को देगी ट्रेनिंग

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में गलतियों को सुधारने के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को टैबलेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर जाकर गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। विद्यार्थियों को बताया वे किस प्रकार मृत व्यक्तियों के नाम हटाकर जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को समझने में आसानी होगी। टैबलेट के माध्यम से सिखाई जाएगी प्रक्रिया सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पहले ही टैबलेट उपलब्ध करवा दिए इन टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों को परिवार पहचान पत्र में सुधार करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इससे विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा और वे अपने आसपास के लोगों की भी इस प्रक्रिया में मदद कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेवाड़ी के संगवाड़ी और खोल गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जागरूकता शिविर लगाए गए। इन शिविरों के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने पूरे प्रदेश में जागरूकता शिविर लगाने की योजना बनाई फैमिली आईडी से छात्रों को मिलते हैं लाभ परिवार पहचान पत्र, जिसे फैमिली आईडी के नाम से भी जाना जाता है,

कश्मीरियों के खिलाफ न जाएं , विनय नारवाल के बर्थडे पर पत्नी हिमांशी ने दिया एकता का संदेश

करनाल। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के दिवंगत लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन पर उनकी पत्नी हिमांशी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे कि वह जहां भी हों, स्वस्थ और खुश रहें। इसके साथ ही हिमांशी ने कहा कि हम देश में शांति चाहते हैं। मैं किसी भी रह की हेट नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती की देश मुसलमान और कश्मीरी के विरुद्ध जाए। आज एक मई को विनय नरवाल का जन्मदिन है। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिमांशी ने भी ब्लड डोनेट किया। विनय नरवाल का 26वां जन्मदिन है। परिवार के सदस्यों ने पहले इस दिन के लिए खास तैयारी की थी और सभी दोस्तों और रिशतेदारों को पार्टी के लिए बुलाना था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। इसलिए परिवार के सदस्यों ने विनय की याद में थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए रक्तदान

शिविर लगाने का फैसला लिया। वहीं, विनय के स्वजन माता आशा, पिता राजेश नरवाल व दादा हवा सिंह ने भी एक सुर में शहीद का दर्जा देने की मांग दोहराई है। पिता ने कहा कि सरकार सोचे, हक बनता है तो मिलना चाहिए। विनय के पिता ने कहा है कि सरकार की ओर से जो भी फंड मिलेगा वे उसे उस संस्थान या संस्था को दान कर देंगे, जिसका नाम सरकार विनय के नाम पर रखेगी। एक भी पैसा वह अपने घर पर नहीं रखेंगे। विनय के ससुर सुनील कुमार ने कहा कि लोगों की आवाज है कि विनय को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इधर शहर की सामाजिक संस्थाएं भी इस मांग को जोर शोर से उठाने लगी हैं। निफा संस्था ने सरकार से मांग रखी है कि विनय की श्रद्धांजलि सभा से पहले उसे शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया जाए। आतंकी हमले में गई थी जान बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इनमें करनाल के नेवी अफसर विनय नरवाल भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले थे। उनकी उम्र 26 साल थी। वे भारतीय नौसेना में अफसर थे। नरवाल की हाल ही में शादी हुई थी। वे छुट्टी पर थे और कश्मीर में घूमने गए थे। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि 26 साल के नरवालकोच्चि में तैनात थे। 16 अप्रैल को अपनी शादी के बाद कश्मीर घूमने गए थे। उनका रिसेप्शन 19 अप्रैल को हुआ था।

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने उनके जन्मदिन पर एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे और वह जहां भी हों स्वस्थ और खुश रहें। हिमांशी ने कहा कि वह देश में शांति चाहती हैं और किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं चाहतीं।

संक्षिप्त डायरी

मणिपुर में दो तस्करों से याबा की 3 लाख गोलियां और नकदी बरामद

इंफाल / भव्य खबर / एजेंसी । मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में मादक पदार्थ के संदिग्ध दो तस्करों को गिर तार कर उनके पास से 35.41 किलोग्राम याबा की गोलियां बरामद की गईं। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को टीओबी यांगौबंग में दो वाहनों को रोका गया, जिनकी तलाशी लेने पर 2.6 लाख रुपए नकद मिले और याबा की करीब तीन लाख गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस को शक है कि वाहन भारत-यांमार सीमा पर मोरेह से चुराचांदपुर जा रहा था। पुलिस ने बताया कि गिर तार किए गए लोगों की पहचान पाओजाथांग किपगेन (30) और कमिनलुन किपगेन (24) के रूप में हुई है। याबा गोलियां भारत में अवैध है। इनमें 'मेथाफेटामाइनइ होता है। पुलिस ने बताया कि एक अन्य अभियान में इंफाल पश्चिम जिले के पटसोई से मादक पदार्थ के संदिग्ध दो तस्करों को गिर तार कर उनके पास से 274.8 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गिर तार लोगों की पहचान केयेनबाम केनेडी सिंह (36) और केसाम सरत सिंह (55) के रूप में हुई है। पुलिस इन दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है।

अफगानिस्तान से भारत जा रहे 150 ट्रकों को पाकिस्तान ने इजाजत दी, अब भारत को लेकर संशय

अमृतसर / भव्य खबर / एजेंसी । पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेकर अफगानिस्तान से भारत जा रहे 150 ट्रकों को वाघा सीमा पार करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला इस्लामाबाद मौजूद अफगानिस्तान के दूतावास के अनुरोध पर हुआ है। हालांकि, अब इस पर संदेह है कि भारत उन्हें वाघा के रास्ते अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) पार करने की इजाजत देगा या नहीं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि ये अफगान ट्रक 25 अप्रैल 2025 से पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और देश के विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर फंसे हुए थे। इन ट्रकों में माल भरा हुआ है, इस ट्रांजिट में भारत ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने फैसले को अफगानिस्तान के साथ भाईचारे के संबंधों के दृष्टिगत लिया है। अफगान दूतावास द्वारा उपलध कराई गई 150 ट्रकों की सूची संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। यदि और कोई ट्रक फंसे हुए हैं, तब उनकी जानकारी भी जल्द साझा करने को कहा गया है, ताकि उन्हें भी वाघा सीमा तक जाने की अनुमति दी जा सके। लेकिन अभी भारत की ओर से इसपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। संशय बना हुआ है कि पाकिस्तान तब इन्हें वाघा से आगे भेजने को तैयार हो जाएगा, लेकिन भारत के अटारी बॉर्डर पर बने आईसीपी पर रिसीव किया जाएगा या नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने व्यापार के लिए एकमात्र जमीनी रास्ते अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) को तत्काल बंद करने का ऐलान किया था। आईपीसी से मात्र पाकिस्तान से ही नहीं, अफगानिस्तान से भी व्यापार होता था। लेकिन अब भारत के ए श न से पाकिस्तान के साथ-साथ अफगानिस्तान से व्यापार पर भी इसका असर हुआ।

भारत में लू के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने का अनुमान

नई दिल्ली / भव्य खबर / एजेंसी । मई में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। आईएमडी के डायरे ट मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, उार प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लू के दिनों की सं या सामान्य से चार दिन ज्यादा रहने का अनुमान है। उधर राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने अप्रैल का 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां बुधवार को दिन का तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके पहले 29 अप्रैल 2014 को 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश में मई महीने में तेज गर्मी पडड्रे का ट्रेंड है। देश में अप्रैल में 72 हीटवेव दिन दर्ज किए गए। राजस्थान और गुजरात में 6 से 11 दिन और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 4 से 6 दिन तक लू चली। आमतौर पर यहां दो से तीन दिन हीटवेव के होते हैं। भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। बीते साल देश में 554 दिन हीट वेव का असर रहा था। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हीट वेव के लिए इन्हें गिनने का अलग तरीका है। मान लीजिए किसी महीने दिल्ली में 10 दिन, राजस्थान में 15 दिन, क्क में 12 दिन और बिहार में 8 दिन हीट वेव रही, तब हीट वेव डे 45 (10+15+12+8) माने जाएंगे।

हिमाचल में कहीं भी कचरा फेंकने वालों के चालान काटे जाएंगे-सभी कॉमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन अनिवार्य

शिमला / भव्य खबर / एजेंसी । हिमाचल की सु खू सरकार ने पहाड़ों को साफ-सुथरा बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहले फैसले में राज्य में आने वाले सभी कॉमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन अनिवार्य किया गया है। दूसरे नियम में पर्यटन स्थलों और पहाड़ों पर कचरा फेंकने वालों के चालान काटे जाएंगे। ये दोनों नियम 29 अप्रैल से लागू हो गए हैं। अब जिस टै सी, टै पो ट्रेवलर, प्राइवेट व सरकारी बस और बाहरी राज्यों के कॉमर्शियल वाहनों में डस्टबिन (कूड़ेदान) नहीं होगा, उसके मालिक को 10 हजार रुपए जुमार्ना देना होगा। वहीं, जो टूरिस्ट पहाड़ों पर या टूरिस्ट प्लेस को गंदा करेगा, उस पर्यटक पर 1500 रुपए का जुमार्ना लगेगा। यह पेनल्टी लोकल लोगों पर भी लागू होगी। बता दें कि हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश और विदेश से हर साल डेढ़ से 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचते हैं। इसमें ज्यादातर टूरिस्ट टै सी, वॉल्वो बसों और टै पो ट्रेवलर से आते हैं। हिमाचल सरकार के फैसले का इन टूरिस्टों पर सीधा असर होगा। सु खू सरकार के आदेश पर हिमाचल पथ परिवहन निगम और टै सी संचालकों ने अपनी गाडिड्रों में डस्टबिन लगाना शुरू कर दिया हैं। हालांकि, नियम लागू जरूर हुआ है, लेकिन अभी लोगों और ड्राइवरों पर सती शुरू नहीं की गई है। इस बारे में शिमला के आरटीओ अधिकारी ने बताया है कि अभी ट्रांसपोर्टरों के चालान नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को डस्टबिन लगाने के लिए जागरूक कर रहे है, ताकि जनता को सरकार के इस नए नियम की जानकारी दी जा सके। एक सप्ताह बाद चालान कटने शुरू हो जाएगा।

युद्ध के लिए उकसा रहे पाकिस्तान ने उरी सहित तीन सेक्टरों में की फायरिंग

जम्मू(एजेंसी)। पाकिस्तान लगातार भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो अक्षम्य हैं। सीमा पर सीजफायर का लगातार उल्लंघन करना और वहां फायरिंग करना पाकिस्तान की आदत में शुमार हो गया है। बुधवार रात को भी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीजफायर तोड़ा गया। पाकिस्तानी सेना ने हल्के हथियारों से कुपवाड़ा, उसी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की.. भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।

बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार सीजफायर उल्लंघन कर रहा है। मंगलवार को भारतीय सेना के उच्च अधिकारी ने हॉटलाइन के जरिए पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को सीजफायर उल्लंघन करने पर चेतावनी भी दी थी। भारतीय सेना की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिकज, 30अप्रैल-1 मई की दरमियानी रात को

पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के हल्के हथियारों से फायरिंग की गई। यह गोलीबारी कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर के आसपास की गई, भारतीय सेना ने भी इसका जवाब तेजी और सटीकता के साथ दिया।इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 अप्रैल को कश्मीर और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों में बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की थी वहीं 27 अप्रैल को भी तुतमार गली और रामपुर सेक्टर में गोलीबारी हुई थी। 28 अप्रैल को पाकिस्तान की तरफ से पुंछ और कुपवाडा सेक्टर में गोलीबारी की गई थी और अगले दिन 29 अप्रैल को अखनूर के परगवाल सेक्टर और चेनाब पोस्ट पर फायरिंग की गई थी। भारतीय सेना ने भी इन सभी चुनौतियों का माकूल जवाब दिया था। बता दें कि 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने 2003 के संघर्ष विराम समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना लगातार इसका उल्लंघन कर रही है। बार-बार होते सीजफायर उल्लंघन को देखते हुए सीमावर्ती गांवों के लोगों ने युद्धकालीन बंकरों को साफ करक उनमें रहना शुरू कर दिया है। भूमिगत बंकर, जिन्हें मोदी बंकर कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान सीमावर्ती निवासियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय के रूप में काम करते हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू का हिमाचल दौरा निरस्त, फिर से तैयार होगा दौरा कार्यक्रम

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का 5 मई को होने वाला हिमाचल प्रदेश का दौरा निरस्त कर दिया है। कई कारणों से यह निर्णय लिया गया है। बुधवार को डीसी शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इस दौरान कल्याणी हैलीपैड से द रिट्रीट तक जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरना था, उन मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा रद्द हो गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति को 7 मई को आईआईटी मंडी की 15 साल की विकासात्मक यात्रा पर रखे गए सम्मेलन में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होना था। वहीं 8 मई को उनका अटल टनल जाने का कार्यक्रम था। राष्ट्रपति के दौरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से कई बड़े अधिकारी आकर स्थिति का जायजा ले चुके थे। आईआईटी मंडी में भी राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही थीं, लेकिन ऐन मौके पर दौरा स्थगित हो गया है। मंडी के स्थानीय एवं प्रबुद्ध लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हों तो देश के प्रथम नागरिक की सुरक्षा हेतु कड़े इंतजाम होने चाहिए और प्रोटोकॉल में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा को देना उसके अधिकारों पर सीधा हमला: मान

अमृतसर (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की आपत्तियों के बाद भी भाखड़ा बांध से हरियाणा को तत्काल 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के फैसले के खिलाफ आप पार्टी पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप के मंत्रियों और नेताओं ने हरियाणा को अतिरिक्त जल आवंटित करने के निर्णय के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों और नेताओं के घरों का घेराव करने की घोषणा की।

आप प्रवक्ता ने कहा, पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा को देना राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है।'' बीबीएमबी भाखड़ा, रणजीत सागर और पोंग बांधों से जल वितरण को नियंत्रित करता है। बीबीएमबी के फैसले पर प्रतिक्रिया देकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बीबीएमबी के माध्यम से राज्य और पंजाबियों के अधिकारों को हरियाणा को हस्तांतरित करने के कदम का विरोध करता है। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारें पंजाब के खिलाफ एकजुट हो गई हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा को कड़े विरोध का सामना करना होगा। पंजाब आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि पार्टी बीबीएमबी को हरियाणा को 8,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने के लिए मजबूर करने के फैसले के खिलाफ बलिदान देने के लिए तैयार है। भाजपा की इस गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। याद रखिए, यह पंजाब है, जिसने इसतरह के कई हमलों को नाकाम किया है।

आप की यह कड़ी प्रतिक्रिया बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को उसकी पेयजल जरूरतों के लिए 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के फैसले के बाद आई है। यह निर्णय बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठक में लिया गया, इसमें राजस्थान और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने हरियाणा के पानी के अनुरोध का समर्थन किया, तथा पंजाब सरकार की आपत्तियों को नजरअंदाज कर कहा कि हरियाणा के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है, क्योंकि राज्य ने पहले ही इस अवधि के लिए अपना हिस्सा ले लिया है। पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर मतभेद का लंबा इतिहास रहा है।

जाति जनगणना की घोषणा पहलगाम आतंकी हमले से लोगों का ध्यान भटकने की कोशिश-संजय सिंह

बलिया (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने जातिवार जनगणना को पहलगाम आतंकवादी हमले की घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया हथकंडा करार देते हुए दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव होते ही भारतीय जनता पार्टी सरकार जातिवार जनगणना को भूल जाएगी।

सपा सांसद संजय सिंह ने जिले के पंडितपुरा गांव में संवाददाताओं से बातचीत में जातिवार जनगणना को लेकर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आप (सरकार) पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) को वापस लेने के लिए किस तरह से हमला करेंगे। आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए क्या करेंगे। पहलगाम में 26 निहत्थे और निर्दोष पर्यटक मारे गए और हमारी धरती पर आकर आतंकवादियों ने हमें चुनौती देने का काम किया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई

करेंगे। ऐसे समय में सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आप (सरकार) जातिवार जनगणना का विषय ले आए।

उन्होंने कहा कि हम जातिवार जनगणना के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग शुरू से जातिवार जनगणना कराने की बात करते हैं, मगर आप (सरकार) ऐसे समय में जाति जनगणना लेकर आए हैं जिससे पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद की घटना से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जनता आपसे सवाल न पूछे। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जातिवार जनगणना की घोषणा तो कर दी लेकिन यह नहीं बताया कि यह काम कितने समय में पूरा होगा। उन्होंने इसे बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई कोरी घोषणा बताते हुए कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया लेकिन इस आरक्षण को लागू करने की दिशा में एक इंच भी कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह सरकार जातिवार जनगणना की घोषणा कर रही है। उसके लिए ना तो बजट का आवंटन किया गया है और ना ही यह बताया जा रहा है कि कितने समय में यह जनगणना पूरी की जाएगी।

आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि जब बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा तो सरकार जातिवार जनगणना को भी भूल जाएगी। यह सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहलगाम में दो हजार से अधिक लोग मौजूद थे। आतंकवादी आए और हत्या कर चले गए। यह खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है। सबसे पहले यह मोदी सरकार की विफलता है। इस पर सरकार को कोई जवाब देना चाहिए। जवाबदेही होनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए, मगर कुछ किया नहीं। प्रधानमंत्री तो इस मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक छोड़कर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे।

बरेली में महिला शिक्षक के अचानक गायब होने से क्यों खुफिया एजेंसियों में हड़कंप

बरेली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही ने पूरे देश की सुरक्षा को बड़े खतरे में डाल दिया। यहां 9 साल तक पाकिस्तान निवासी एक महिला बेसिक शिक्षा विभाग की मेहरबानी से नौकरी कर रही थी। खुलासा होने पर विभागीय अधिकारी बेहद गंभीर मामले को डीएम या फिर एसएसपी को बताने की जगह दबाकर बैठे रहे। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद महिला रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। खुफिया एजेंसियों सहित पुलिस की 8 टीमें महिला को ढूंढने में जुटी हैं।

बेरली जिले के डीएम ने दो सीनियर पीसीएस अधिकारी एडीएम और सिटी में मजिस्ट्रेट की ज्वाइंट जांच कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच का आदेश दिए है। पाकिस्तान निवासी शुमायला खान को लेकर बरेली का पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला बेहद परेशान है। वजह जहां पाकिस्तान की हरकतों को लेकर पूरे देश में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं वहीं बरेली में पाकिस्तानी महिला शुमायला के गायब होने से हड़कंप मच गया।

पाकिस्तान निवासी शुमायला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर साल 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग में मास्टर की नौकरी हासिल कर ली। माधौपुर सरकारी स्कूल में नौकरी देकर 9 साल तक विभागीय अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए शुमायला को अभयदान देते रहे। 2 साल पहले भी जब शुमायला के पाकिस्तानी होने का मामला सामने आया तब विभागीय अधिकारी जांच के नाम पर डीएम या एसएसपी को बताने की बजाय फाइल को अपने पास लटकाए रहे। कुछ दिन पहले जब मामला ने बेहद तूल पकड़ा, तब शुमायला बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने के बाद रहस्य में ढंग से देश में गायब हो गई।

कांदिवली में रक्तदान शिविर के आयोजन में पहुंचे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी

कांदिवली/ भव्य खबर/ अमित मिश्रा। श्री सागर जैन मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का विशाल पैमाने पर आयोजन कांदिवली रिक्रिएशन क्लब, शान्तीलाल मोदी मार्ग, कांदिवली- पश्चिम में किया गया। इस रक्तदान शिविर में उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज कराते हुए रक्तदाताओं और शिविर के आयोजकों का हौंसला बढ़ाया। जनसेवक गोपाल शेट्टी ने रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को अपने हाथों सर्टिफिकेट प्रदान किया और भविष्य में भी समय-समय

पर रक्तदान करते रहने की सबसे अपील की ताकि जरूरतमंद नागरिकों का जीवन बचाया जा सके। इस अवसर पर जनसेवक गोपाल शेट्टी के साथ धवल वोरा और संस्था के सभी पदाधिकारीऔर कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जातीय जनगणना के लिए सोनिया के सामने कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते थे लालू: गिरिराज सिंह

राहुल गांधी लंबे समय तक सत्ता में थे जाति गणना क्यों नहीं कराई

पटना (एजेंसी)। मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले पर बिहार में बयानबाजी शुरु हो गई है। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही बैठक में भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पीएम मोदी के इस फैसले से विपक्ष तक खुश है। लालू के ÷कान पकड़कर जातीय जनगणना करवाएंगे÷ वाले बयान पर गिरिराज ने पलटवार कर कहा कि जिंदगी भर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के सामने कान पकड़कर उठक-बैठक करते रहे, अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। यह वहीं लालू यादव हैं जो कभी कांग्रेस के साथ मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने ही वर्षों से लंबित सामाजिक न्याय की मांग को पूरा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने ओबीसी को सरकारी संरक्षण दिया। उन्होंने एससी के अधिकारों को कोर्ट में और मजबूत किया और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण देकर न्याय सुनिश्चित किया। केंद्रीय मंत्री सिंह ने राहुल गांधी पर निशाने साधते हुए कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। इतिहास गवाह हैं कि कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक न्याय का विरोध किया है, चाहे वह नेहरू हों या इंदिरा गांधी या फिर उनके पिता राजीव गांधी। वहीं उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने पीएम मोदी के जातीय जनगणना करनेके निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले पीढ़ियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह निर्णय लिया है। इस निर्णय से विकास की गति बढ़ेगी और परिवारवाद की जमींदारी करने वालों का जमीन खिसक जाएगी। इसतरह के लोग ज्यादा तक दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी जैसे लोग सिर्फ भौकाल बनाते हैं, इनका करनी-धरनी कुछ नहीं है। राहुल गांधी लंबे समय तक जब सत्ता में थे तब उन्होंने जाती गणना क्यों नहीं कराई।

मप्र, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में आंधी और बारिश, मैहर-डिंडौरी में ओले गिरे...

-शाजापुर में 73 किमी की रफ्तार से हवा चली

-मोबाइल टावर गिरा, 4 मवेशी मरे

नई दिल्ली/भोपाल (एजेंसी)। मई में भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में आंधी और बारिश हो रही है। डिंडौरी में गुरुवार दोपहर डेढ़ बजे आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, मैहर, सिवनी और बालाघाट में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। मैहर के कई इलाकों में ओले गिरे भी हैं। इससे पहले बैतूल के पिपरिया गुरुवा गांव में आंधी से 100 फीट ऊंचा बीएसएनएल टावर गिर गया। हादसे में चार बैल मारे गए, जबकि दो घायल हो गए। वहीं, इंदौर में शाम को तेज हवा चलने से पेड़ गिर गया। नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, हरदा, रतलाम, खंडवा, देवास, सीहोर, अनूपपुर, डिंडौरी और नर्मदापुरम में हल्की बारिश हुई। तेज आंधी भी चली। शाजापुर में सबसे ज्यादा 73 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चली। हरदा में इसकी रफ्तार 69 किमी, उज्जैन में 58 किमी, आगर-मालवा में 42 किमी, इंदौर में 65 किमी, नीमच-अनूपपुर में 45 किमी, सीहोर में 41 किमी, सिवनी में 36 किमी प्रतिघंटा रही।

रायपुर में शेड गिरा, कारें दबी

रायपुर में शाम होते ही अचानक तेज धूल भरी आंधी चली। करीब 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने से कई जगह पेड़ और होर्डिंग्स गिरे हैं। आंधी-तूफान से सिमगा में पूरा टोल प्लाजा ही तहस-नहस होकर सडक़ पर गिर गया। वहीं देवेंद्र नगर में सडक़ पर बना शेड गिर गया। इसमें कई कार भी नीचे दब गई। जेसीबी की मदद से टीन शेड हटाने का काम किया गया। आंधी-बारिश के कारण प्रदेश में दिन का तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिरा है। इस वजह से गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मई के पहले सप्ताह में बारिश-ओले

मप्र में मई महीने में भीषण गर्मी पडऩे का ट्रेंड है। पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़े एमपी के जिलों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। इस बार भी ऐसी ही गर्मी पड़ सकती है। हालांकि, मई के पहले सप्ताह में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। आखिरी सप्ताह में सबसे ज्यादा तपिश होगी।

मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी के अलावा ये अभिनेत्री निभाएगी पुलिस का किरदार

साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म मर्दानी में अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने पुलिस का दमदार किरदार निभाया था। ये फिल्म काफी कामयाब रही थी। फिल्म की कामयाबी के बाद रानी मुखर्जी मर्दानी 2 में नजर आईं। यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रही। अब फैंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। साल 2024 में खबर आई कि फिल्म निर्माता मर्दानी 3 पर काम कर रहे हैं। खबर के मुताबिक फिल्म मर्दानी 3 की शूटिंग इसी साल के शुरुआत में शुरू हो चुकी है। फिल्म अगले साल 2026 में होली के मौके पर रिलीज होगी।

जानकी बोदीवाला होंगी फिल्म का हिस्सा

वेबसाइट के मुताबिक अभिनेत्री जानकी बोदीवाला भी फिल्म मर्दानी 3 में अहम किरदार अदा करेंगी। जानकी बोड़ीवाला ने फिल्म शैतान में अच्छा रोल निभाया था। इससे रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्होंने जानकी बोदीवाला को फिल्म में अहम किरदार दिया है। वह फिल्म में एक पुलिस का किरदार निभाएंगी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में हो रही है। खबर है कि मर्दानी 3 दोनों फिल्मों से जबरदस्त होगी। पहले की फिल्में सामाजिक मुद्दों पर आधारित थीं। उसी तरह यह फिल्म भी जरूरी सामाजिक मुद्दों पर होगी।

जानकी बोदीवाला का बॉलीवुड में दमदार किरदार

जानकी बोदीवाला ने बॉलीवुड में शैतान फिल्म से डेब्यू किया था। इससे पहले वह गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थीं। अब वह बॉलीवुड में मर्दानी 3 में अहम रोल अदा करने वाली हैं।

मर्दानी 3 यशराज फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली है। इस बैनर तले चार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। सैयारा 18 जुलाई, वार 2 दो अगस्त, अल्फा 25 दिसंबर और मर्दानी 3 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली हैं।

कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर बोलीं रकुल प्रीत

रकुल प्रीत सिंह के एक्टिंग करियर को लगभग 15 साल हो चुके हैं। वह कई रोमांटिक फिल्मों का हिस्सा बन चुकी हैं। रकुल को फैंस उनके नेचुरल लुक के लिए भी काफी पसंद करते हैं। हाल ही में कॉस्मेटिक सर्जरी, प्रोसिजर को लेकर रकुल ने अपना नजरिया साझा किया।

भगवान ने मुझे ठीक-ठाक शक्ल दी

हाल ही में एक इवेंट में रकुल प्रीत सिंह को देखा गया। इंस्टेंट बॉलीवुड से की गई बातचीत में वह बताती हैं कि उन्हें कभी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का ख्याल नहीं आया। रकुल कहती हैं, 'भगवान ने मुझे ठीक-ठाक शक्ल दी है, इसलिए ऐसी बातों के बारे में सोचा नहीं है।' बताते चलें कि पिछले दिनों रकुल को पैपराजी ने मुंबई में एक गाड़ी से उतरते देखा तो उन्होंने अपने होंठों को छुपा लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखकर यूजर्स ने कहा था कि रकुल ने होंठों पर कोई कॉस्मेटिक प्रोसिजर करवाया है या फिर फिलर (एक तरह का प्रोसिजर है, जिससे होंठ उभरे हुए नजर आते हैं) का यूज किया है।

कॉस्मेटिक प्रोसिजर को गलत नहीं मानती

आगे रकुल कहती हैं, 'हां, अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए पहले कई बीमारियों का इलाज नहीं था, अब है। ऐसे ही अगर कोई सुंदर दिखने के लिए कॉस्मेटिक प्रोसिजर करवाना चाहता है तो इसमें गलत कुछ नहीं है।'

इन फिल्मों में नजर आएंगी रकुल

रकुल के करियर फ्रंट की बात करें तो वह कुछ दिन पहले अर्जुन कपूर की फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में नजर आईं। इस साल वह एक साउथ फिल्म 'इंडियन 3' कर रही हैं, साथ ही 'दे दे प्यार दे-2' में भी नजर आएंगी। इस फिल्म के पहले पार्ट में रकुल की जोड़ी अजय देवगन के साथ बनी थी।

करियर की शुरूआत में मुझे बदकिस्मत कहा जाता था

तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकीं अभिनेत्री श्रुति हासन ने अपने करियर के शुरूआती दिनों को याद करते हुए बात की। फिल्मफेयर के साथ हालिया बातचीत में अभिनेत्री ने बताया कि कैसे उन्हें अपने करियर की शुरुआत में बदकिस्मत माना जाता था। क्योंकि उनकी पहली दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थीं। अभिनेत्री ने कहा कि तेलुगु में यह मिथक था कि मैं बदकिस्मत हूं, क्योंकि मेरी पहली दो फिल्में नहीं चलीं। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उन दो फिल्मों में एक ही हीरो था। लेकिन लोग कहते थे कि उन्हें मैं नहीं चाहिए। श्रुति ने साल 2011 में सिद्धार्थ के साथ फिल्म 'अनागनागा ओ धीरुदु' और रोमांटिक ड्रामा 'ओह माय फ्रेंड' में काम किया था। ये उनकी पहली दो फिल्में थीं। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं। अभिनेत्री ने आगे बताया कि फिर पवन कल्याण सर ने मुझ पर भरोसा जताया और मेरा पूरा करियर बदल गया। अचानक बॉम्बे दिखने लगा, और तमिल दिखने लगा। एक्ट्रेस ने कहा कि यह सिर्फ लोगों की वजह से है और वे आप पर कितना भरोसा करते हैं। यह क्रिएटिव रूप से भी तब सामने आता है जब उन्हें लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं। पवन कल्याण ने 2012 में आई 'गब्बर सिंह' में श्रुति हासन के साथ काम किया था।

जयदीप ने बताया कैसे संभालते हैं फेम का प्रेशर

अपने अभिनय से इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले अभिनेता जयदीप अहलावत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज 'ज्वेल थीफ' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है और इसे लोगों के मिले-जुले रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। इससे पहले अभिनेता को उनके शो पाताल लोक सीजन 2 के लिए काफी प्रशंसाएं मिलीं और उनके अभिनय को काफी सराहा गया। अब अभिनेता ने सीरीज के किरदार हाथी राम चौधरी को लेकर बात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे 'पाताल लोक' ने उनके जीवन में काफी बदलाव लाया है।

हाल ही में बातचीत में जयदीप अहलावत ने अपने सबसे मशहूर किरदार हाथी राम चौधरी को लेकर बात की। अभिनेता ने कहा, मुझे अपने आज तक निभाए गए सभी किरदार पसंद हैं। लेकिन बेशक जिसने मेरे करियर को सबसे अधिक प्रभावित किया, वह पाताल लोक था। हाथी राम ने मेरे लिए और लोगों के मुझे एक अभिनेता के रूप में देखने के तरीके में बहुत कुछ बदल दिया।

किरदार के प्रति रहना है ईमानदार

इस दौरान जयदीप अहलावत ने बैक-टू-बैक हिट परफॉर्मेंस देने के दबाव के बारे में भी बात की। अभिनेता ने कहा, यह दबाव हमेशा बना रहता है। इसलिए मैं खुद को यह याद दिलाता रहता हूं कि किरदार के साथ ईमानदार रहना है। बाकी सब सिर्फ शोर है।

हालिया रिलीज 'ज्वेल थीफ' में अपने किरदार राजन औलाख के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा, इसमें स्वभाव, तड़क-भड़क और शरारत या खुराफात का एक संकेत है। यह स्टाइलिश है, लेकिन इसमें परतें भी हैं। इसकी अप्रत्याशिता और नयेपन ने मुझे सबसे अधिक उत्साहित किया। भले ही पहले भी मैंने इंटेंस और इस तरह के किरदार निभाए हों, लेकिन यह भूमिका निभाना मजेदार था।

'द फैमिली मैन सीजन 3' में दिखाई देंगे जयदीप अहलावत

वर्कफ्रंट की बात करें तो जयदीप अहलावत की हालिया रिलीज 'ज्वेल थीफ- द हीस्ट बिगिन्स' है। इसमें उनके साथ सैफ अली खान, कुणाल कपूर और निकिता दत्ता भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आई हैं। वो अब मनोज बाजपेयी की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' में साथ नजर आएंगे।

साई को रिलेशनशिप में मिला धोखा

हालिया रिलीज 'ग्राउंड जीरो' में इमरान हाशमी के साथ नजर आईं अभिनेत्री साई तम्हणकर ने एक्टिंग से परे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, प्यार, विश्वासघात और धोखे को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने रोमांटिक रिलेशनशिप को प्रभावित करने वाले कुछ इमोशनल पैटर्न के बारे में भी अपने विचार रखे।

साई को मिला रिश्ते में धोखा

हॉटरफ्लाई के साथ हालिया बातचीत में अभिनेत्री साई तम्हणकर ने अपने एक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए कहा, हां, बेशक मुझे धोखा मिला है। कम उम्र में धोखा दिया गया था। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत पहले मेरे बहुत बुरे रिश्ते रहे हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मुझे यह भी लगता है कि एक व्यक्ति के साथ रहना थोड़ा अप्राकृतिक है। मेरा मानना है कि चीट करने पर खुले तौर पर वापस आकर अपने पार्टनर को यह बताने की हिम्मत रखो कि मैंने यह किया है। आप दोनों इसके साथ शांति बनाए रखें।

साई ने बताया बहस के दौरान क्या करती हैं लड़कियां

बहस के दौरान अक्सर अनसुलझे मुद्दों के फिर से उभर आने पर साई का कहना है, तब लड़की को हर लड़ाई में यह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़कियां ऐसा करती हैं। हर लड़ाई में, अगर कोई पुरानी बात है तो। मैंने भी यह किया है, इसलिए मैं यह कह रही हूं। वह ऐसा करती है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कमिटेड रिलेशनशिप में चिंता बनी रहने और धोखे का डर सा लगा रहने पर अभिनेत्री ने कहा, जब कोई रिश्ता बनता है, तो वह बेचैनी या वह भावना अभी भी जीवित रहती है। लेकिन यह वाकई में दूरी नहीं होती है।

2013 में की शादी, दो साल बाद हो गई अलग

साई तम्हणकर ने पहले विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट अमेय गोसावी से शादी की थी। दोनों ने 15 दिसंबर 2013 को शादी की, लेकिन 2015 में आपसी सहमति से अलग हो गए। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने अलग होने का कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया।

दूल्हा बनने के अलावा राजकुमार राव ने इन फिल्मों में निभाया दमदार किरदार, खूब हुई तारीफ

राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में शादी में हो रही मुश्किलों को दिखाया गया है। फिल्म में राजकुमार राव की शादी होने में कई अड़चनें आती हैं। राजकुमार राव की कई फिल्में हैं जिनमें शादी के मुद्दे को दिखाया गया है। इन फिल्मों में शादी में जरूर आना, बधाई दो और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो शामिल हैं। इस खबर में हम आपको राजकुमार राव की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें उन्होंने दूल्हे के अलावा दूसरे किरदार निभाए हैं।

भीड़

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म भीड़ में कोरोना महामारी के बाद उपजे हालात को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी को प्रवासी श्रमिकों को सीमा पार करने से रोकने का काम सौंपा गया है। पुलिस वाला जब लोगों की पीड़ा को देखता है तो वह लोगों की मदद करने लगता है। पुलिस अफसर के किरदार को राजकुमार राव ने अच्छे से निभाया है।

छलांग

साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म छलांग एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा है। फिल्म में राजकुमार राव ने एक खेल अध्यापक की भूमिका निभाई है। फिल्म में वह एक आलसी प्रशिक्षक हैं, जो नौकरी में बने रहने के लिए न्यूनतम काम करते हैं। फिल्म में तब मजा आता है जब एक नया शिक्षक उनकी नौकरी और उनसे प्यार करने वाली महिला को छीनने की धमकी देता है। फिर राजकुमार राव एक्शन मोड में आते हैं।

न्यूटन

साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन में राजकुमार राव ने रिटर्निंग ऑफीसर का किरदार निभाया है। फिल्म में राजकुमार राव को एक ऐसे इलाके में चुनाव की ड्यूटी के लिए भेजा जाता है जो राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। राजकुमार राव अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने अच्छी आदाकारी की है। फिल्म को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स और नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के अलावा कई दूसरे अवॉर्ड्स भी मिले थे।

अलीगढ़

साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म अलीगढ़ एक प्रोफेसर पर आधारित थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी अहम किरदार में थे। इस फिल्म में राजकुमार राव ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मराठी भाषा के प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास रामचन्द्र सिरस पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया है कि एक प्रोफेसर जिसकी फीलिंग दूसरे लोगों से अलग थी, उन्हें कितनी दिक्कतें हुईं। फिल्म में राजकुमार राव एक सच्चे पत्रकार की भूमिका निभाते हैं।

शाहिद

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म शाहिद एक वकील की कहानी पर आधारित थी। शाहिद आजमी जिन पर पूर्व आतंकवादी कार्यकर्ता का इल्जाम लगता है, वह बाद में एक वकील बन जाते हैं। वह उन लोगों के लिए न्याय पाने के लिए लड़ते हैं, जिन्हें आतंकवाद के झूठे आरोप में दोषी ठहराया गया है। इस किरदार को राजकुमार राव ने बखूबी निभाया है। फिल्म की खूब सराहना हुई थी।

वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में सिद्धार्थ संग शामिल हुईं तमन्ना

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की आगामी फिल्म वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट एक पौराणिक थ्रिलर फिल्म है, जिसको शॉर्ट में वीवन नाम दिया गया है। इस फिल्म में अब सिद्धार्थ संग एक साउथ अभिनेत्री की एंट्री हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग जून 2025 में शुरू होगी और यह फिल्म 2026 में जाकर रिलीज होगी। इस फिल्म में तमन्ना एक महत्वपूर्ण और दमदार किरदार निभाएंगी। वह सिद्धार्थ के साथ मिलकर मध्य भारत की पौराणिक कहानियों की दुनिया को पर्दे पर लाएंगी। इसके लिए दोनों कलाकार प्रशिक्षण भी लेंगे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक अमृता आर पंडित द्वारा साई प्रिंटिंग प्रेस, बी- 868, न्यू अशोक नगर दिल्ली 110096 से मुदित तथा ए-115, गली नंबर 13, नई अशोक नगर, दिल्ली 110096 से प्रकाशित।
संपादक - अमृता आर पंडित, मो 8587969284, Mail ID - live18newsnetworktv@gmail.com सभी विवादों के न्याय क्षेत्र दिल्ली न्यायालय में होगा।